[श्री राम शरण]

महोदय ने लिखा है कि क्लास १ और क्लास २ की नौकरियों का जहां तक सम्बन्ध है उनमें इनका रिप्रिजेंटेशन नैलेजिबल है, न के बराबर है । जहां तक आगे भविष्य का सम्बन्ध है, क्लास १ और क्लास २ में इनके रिप्रिजेंटेशन का सम्बन्ध है, उसके बारे में भी आशा नहीं बंधती है और कहा जाता है कि प्रगति असन्तोषजनक है । क्लास ३ में जो प्रतिशत होना चाहिये, वह भी नहीं है, उसमें भी उनको पर्याप्त संख्या में नहीं लिया गया है । जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है, उनको तो क्लास ४ तक की नौकरियों में भी समावेश बहुत कम मिल सका है ।

15 hrs.

एक तरफ तो उनको तीसरे और चौथे दरजे की भी नौकरियां नहीं मिलतीं । दूसरी तरफ यदि हम एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज से जो आंकड़े मिलते हैं उनको देखें तो उनसे पता चलता है कि सन् १९५८ के अन्त में एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में १,२९,५९९ लोग ऐसे थे जो बेकार थे और जो नौकरी चाहते थे, जिनमें से १४,६७८ मैट्रिकुलेट और १,१६४ ग्रेजुएट थे । यह संख्या अनुसूचित जातियों के बारे में है और जहां तक आदिवासियों का सवाल है . .

Mr. Speaker: The hon. Member may continue next day. Now we will take up the motion by Shri Vajpayee.

15·01 hrs.

MOTION RE: NAGA HILLS AND TUENSANG AREA

Shri Tyagi (Dehra Dun): May I raise a point of order?

Mr. Speaker: Let Shri Vajpayee move his motion. Then I will permit the hon. Member to raise his point of order.

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने १ अगस्त को नागा हिल्स तथा त्वेनसांग एरिया के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है उस पर विचार किया जाए ।

Mr. Speaker: Now what is the point of order?

Shri Tyagi: This discussion is covered by Chapter XIV of the Rules of Procedure and Conduct of Business. Rule 184 reads.

> "Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion of a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker."

Here you are giving your consent. Therefore that rule has no application here. But, then, rule 186 says:

> "In order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely:
>
> (i) it shall raise substantially one-definite issue;....."

It further goes on to say:

> "(vii) it shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session;"

As the Prime Minister had announced the other day, the agreement with the Naga representatives is to come in the shape of an amendment to the Constitution, and we shall have a full-fledged debate on this issue. The discussion of the same subject now is actually anticipating that discussion. I submit, therefore, that under this rule this cannot be permitted.

There is another point. It is a matter which directly pertains to the Constitution. In the matter of the Constitution the House can give its verdict only under certain conditions like a majority of the total members of the House and two-thirds of the

members present and voting. Now, if the very same issue is decided today and vote is taken in favour of it or against it, that will amount to the Parliament committing itself on a issue pertaining to the Constitution without following the restrictions prescribed in the very same Constitution.

Under these circumstances, I submit that you might be pleased to declare it out of order because, if we are going to have a discussion very soon, this will only be anticipating that discussion.

Shri Vajpayee: The point of order raised by my hon. friend, Shri Tyagi, is on a motion which you have admitted, a motion which has been agreed to by the Prime Minister. Also, no decision is going to be taken on the motion; no vote will be taken and no verdict will be recorded. Moreover, I do not think that the Government is going to bring forward an Amending Bill in this session. Even then, that particular rule of the Rules of Procedure cannot be stretched to that extent that no subject which is to be discussed later can be raised in the House now. If the rule is to be interpreted in this manner, then there will be no discussion on any important matter.

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): As has been pointed out by the hon. Member, I had agreed to this discussion and I had not thought of any technical or other objections to this motion. I cannot say whether any Bill for the amendment of the Constitution will be brought in this House in this session or not; I cannot commit myself on that. I have no objection to have a discussion on this matter.

Mr. Speaker: Shri Tyagi has raised a point of order that this motion is in anticipation of a discussion which is likely to take place in the same session. We hear reliably from the hon. Prime Minister, who will introduce that Bill in due course, that there is no chance of its being introduced now. Further, I do not want to apply that rule very strictly. Also, the motion had been admitted already and I had agreed that it could be discussed in this session. If an hon. Member has moved a motion and at that time the Government have a proposal to make a motion in this House, that is not anticipating a motion and that cannot stand in he way of this motion. We cannot compel them to move a motion. So far as the constitutional aspect is concerned, it is not as if we are taking the verdict of the House. The Bill can be brought next session. Therefore, this motion is quite in order. Now Shri Vajpayee. Hon. Members will have 15 minutes each because only two hours have been allotted for this.

Shri Vajpayee: I hope I will have 30 minutes.

Mr. Speaker: No, because he has the right of reply.

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने १ अगस्त को जो वक्तव्य दिया उस वक्तव्य के द्वारा एक पृथक् नागा राज्य स्थ पित करने के निर्णय की घोषणा की गयी है । इस राज्य का नाम नागालैण्ड होगा । इसकी अलग विधान सभा होगी, मन्त्रिमण्डल होगा, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसका अपना अलग संविधान होगा ।

मुझे खेद है, प्रधान मन्त्री जी ने सदन के सामने जो वक्तव्य दिया उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि इस नागालैण्ड का अपना अलग संविधान होगा । यह बात समाचार पत्रों द्वारा हमें पता हुई और बाद में इसकी पुष्टि भी की गयी । मैं नहीं समझता कि संसद् को इस बात को न बताने का कारण क्या था । लेकिन एक अलग राज्य बने और उसका अपना अलग संविधान हो, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर इस

[श्री वाजपेयी]

सदन को और देश को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये ।

जो नया नागा राज्य बनेगा, इसकी आबादी मुश्किल से चार लाख के करीब होगी । इसकी आमदनी भी सालाना पांच लाख से अधिक नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, आपने शायद ही कभी ऐसा सुना हो कि साढ़े तीन लाख चार लाख की आबादी और पांच लाख वार्षिक आमदनी का एक अलग राज्य बनाया जाए । इस प्रकार का राज्य बनाना, मैं समझता हूं, अकल्पनीय है, हास्यास्पद है । मगर जो चीज नहीं होनी चाहिये और जो कहीं हुई नहीं है, वह हमारे देश में हो रही है, क्योंकि शायद सरकार न तो प्रेम से समझा बुझा कर लोगों को सीधी राह पर ला सकती है और न दण्ड के द्वारा, भय के द्वारा, अगर किसी वर्ग या समूह में विकार पैदा हो गया है तो उसका परिष्कार कर सकती है ।

और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि नागा राज्य भारत के सीमान्त पर बनेगा । एक ओर चीन है, पूर्वी पाकिस्तान है, बर्मा की सीमा लगी हुई है । यह एक ऐसा छोटा सा राज्य होगा जो कि आर्थिक दृष्टि से केन्द्र पर हमेशा के लिये बोझा बन जाएगा और जो सामरिक दृष्टि से भी देश की सुरक्षा के मार्ग में बाधक बनेगा ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस सम्बन्ध में अपना जो मन्तव्य प्रकट किया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं उद्धृत करता हूं :

"another factor relevant from the point of view of national security is the size and resources of the border States. While the primary responsibility for defence arrangements must be that of the Central Government, a considerable burden relating to security arrangements must be borne by the State. It is, therefore, important that a border State should be a well-administered, stable and resourceful unit, capable of meeting the emergent problems arising out of military exigencies. This means that normally it would be safer to have on our borders relatively larger and resourceful States rather than small and less resilient units."

लेकिन नागाओं का एक अलग राज्य बनाने का फैसला कर लिया गया । मैं समझता हूं कि असम के इन आदिवासी क्षेत्रों मे केवल नागा लोग ही नहीं रहते और भी आदिवासी जातियां रहती हैं मगर राज्य केवल नागाओं के लिये बनाया जा रहा है । इसका असर दूसरे आदिवासियों पर क्या होगा ? प्रारम्भ से वहां एक हिल स्टेट बनाने की मांग की जा रही है । राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी उस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है । यूनाइटेड खासी एण्ड जयन्तिया हिल डिस्ट्रिक्ट्स और गारो हिल डिस्ट्रिक्ट्स, इनकी आबादी नागा हिल डिस्ट्रिक्ट्स से ज्यादा है और उन्होंने सन् १९५७ में यह मांग भी की थी कि एक पहाड़ी राज्य बनाया जाय मगर वह राज्य नहीं बनाया गया । मैं समझता हूं कि वह एक ठीक कदम था । लेकिन अब यह जो एक अलग नागा राज्य बनाया जा रहा है तो उसकी जरूरत क्या है ? शायद इसका एक ही कारण है कि कुछ नागा लोगों ने पिछले अनेक सालों से देश के खिलाफ बगावत की है, विद्रोह का झण्डा उठाया है और हथियारों और हिंसा के बल पर अपनी बात को मनवाने की कोशिश की है । हमारे जवानों को गोली का निशाना बनाया है और जो देशभक्त नागा हैं, सरकार के प्रति वफादार हैं उनको भी इन विद्रोही नागाओं के हाथों संघातिक संकटों का सामना करना पड़ा है । ऐसी स्थिति में एक अलग राज्य बनाना यह पृथकतावाद को इनाम देना है और विद्रोहियों को हिंसा और विनाश के लिये भड़काना है । यह अलग राज्य नहीं बनाया जा रहा मानो सरकार बगावत करने वालों के सामने घुटने टेक रही

है । मैं नहीं समझता कि देश में एक अच्छी परम्परा का श्रीगणेश किया जा रहा है । पृथक् नागा राज्य की स्थापना एकीकरण पर विघटन की विजय है, शान्तिपूर्ण निर्माण पर हिंसा की और ध्वंस की विजय है । देशभक्ति और राष्ट्र निष्ठा पर बगावत और गद्दारी की विजय है ।

मैं समझता हूं कि हमें इस बात का भी विचार करना चाहिये कि उस क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण देश में अन्य जो आदिवासी बन्ध रहते हैं उन पर इस पृथक् राज्य के निर्माण की प्रतिक्रिया क्या होगी । देश में अनेक भाग ऐसे हैं जहां कि आदिवासी रहते हैं । अभी मध्य प्रदेश से समाचार आया है कि वहां रायपुर के निकट एक समानान्तर सरकार बना ली गई । कोई हमारे एक आदिवासी बन्धु प्रधान मन्त्री बन बैठे और वह अपनी एक पतरी सरकार चला रहे थे । बाद में उन्हें पकड़ लिया गया । मगर इस प्रकार की भावनाएं और भी बल पकड़ेंगी और मैं नहीं समझता कि यह देश के लिये ठीक होगा ।

इस बात से सभी सहमत हैं कि जो भी आदिवासी बंधु हैं, नागा लोग हैं उन्हें अपने रहन सहन को और अपने जीवन के रंग ढंग को सुरक्षित रखने और उसके विकास करने का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि उनका रंग ढंग, उनकी संस्कृति, कुछ अंशों में, हम से श्रेष्ठ संस्कृति है और उन्होंने उन जीवन मूल्यों की रक्षा की है जो कि प्राचीन काल में हमारे साथ थे । पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने के कारण हम ने उनको छोड़ दिया था । मैं प्रधान मंत्री जी की इस बात से १०० फीसदी सहमत हूं कि उन्हें अपनी सेकेंड रेट कौपी नहीं बनाना चाहिए, सेकेंड रेट क्या वह तो थर्ड रेट कौपी होगी क्योंकि सेकेंड रेट कौपी तो हम ही हैं । पश्चिम के आधार पर अगर हम उनको बनायेंगे तो उन का रूप बिगड़ जायगा । मैं इस बात से सहमत हूं कि हम उन के मामलों में दखल न दें लेकिन उन्हें अकेले भी नहीं रखा जा सकता । उन्हें "म्युजियम पीसेज" की तरह से सुरक्षित भी नहीं रखा जा सकता । हलके हलके उनकी विविधताओं और विशेषताओं की रक्षा करते हुए हमें उन्हें राष्ट्रीय जीवन के साथ घुलाना-मिलाना होगा ।

मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान परिषद् ने जो निर्णय किया के सिक्स्थ शैड्यूल के अन्तर्गत रीजनल और डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर ऑटोनमस बौडीज देंगे तो मैं समझता हूं कि वह भी इसी दृष्टि से किया था कि उनकी विविधताओं की रक्षा भी हो जाय, हम उन के मामलों में दखल भी न दें और हलके हलके वे हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रवाह के साथ मिल जांय । उस समय भी कुछ सदस्यों ने आपत्ति की थी कि इस प्रकार की आटोनमस बौडी देना यह विघन को बढ़ावा देगा । मगर बारदोलई कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें संविधान परिषद् ने स्वीकार कर लिया और ऑटोनमस बौडीज बन गयीं । पर उनका परिणाम क्या हुआ ? विद्रोह दबा नहीं । उन्हें निकट नहीं लाया जा सका और ऑटोनमस बौडीज को सफलतापूर्वक चलाना भी सम्भव नहीं हुआ । बाद में इन लोगों की तरफ से मांग की गई कि जो त्वेनसांग का ऐरिया है उसको नागा हिल्स के साथ मिला दिया जाय और हमने एक यहां विधेयक भी पास किया जिसके अनुसार त्वेनसांग ऐरिया नागा हिल्स में मिल गया । उस समय यह आशा प्रकट की गई थी कि अब नागा प्रदेश में शान्ति हो जायेगी, मगर शान्ति स्थापित नहीं हुई । अब यह तीसरा कदम है कि एक नया राज्य बनाया जा रहा है । ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सरकार ऐसी शक्तियों के सामने जानते हुए या न जान कर भी झुकती जा रही है जो देश के बाहर जाना चाहते हैं, जिन्हें देश के प्रति निष्ठा नहीं है और जो देश की एकता में विश्वास नहीं करते हैं ।

यह बात सभी जानते हैं कि अंग्रेजी राज्य ने नागा प्रदेश को हम से अलग रखा, चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दीं । अंग्रेजों ने

[श्री व.जपेयी]

कुचक्र किया था कि भारत से जाते जाते वह नागा प्रदेश को आजाद बनाते जांय और जो आखिरी गवर्नर था आसाम का उस ने इस सम्बन्ध में आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। जो मैदान के लोग थे वे नागा प्रदेश में जा नहीं सकते थे और वहां पर केवल विदेशी मिशनरी जा सकते थे और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे नागा बंधु हम से दूर चले गये। मगर यह बात तो १९४७ की है। आज हम १९६० की चर्चा कर रहे हैं। हम ने इन १३ वर्षों में क्या किया? हम उन्हें निकट नहीं ला सके। हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे यह विश्वासपूर्वक कोई नहीं कह सकता और हमारे प्रधान मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है कि नागा प्रदेश में शान्ति हो जायगी। अब अगर शान्ति नहीं स्थापित होगी तो फिर यह प्रथक नागा प्रदेश बनाने का लाभ क्या होगा? हम इतनी बड़ी कीमत चुकाने जा रहे हैं। देश में एक अलग और गलत परम्परा पैदा कर रहे हैं। डाक्टर आवो जो यहां पर आये थे उन्होंने भी कहा है कि जो नागा लैंड की मांग है यह कम से कम है और यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वे कब तक संतुष्ट रहेंगे। ऐसे में प्रवृत्ति होती है अपनी मांगों को बढ़ाने की और उसके ऊपर सरकार जो उदारता दिखाती है और हमारे प्रधान मंत्री जो विशाल हृदयता का परिचय देते हैं तो उसका गलत अर्थ लगाया जाता है और लोग समझने लगते हैं कि सरकार कमजोर है और अगर इनको थोड़ा और दाबाया जाय तो शायद वह और भी हमारी मांग को मान लेंगे। इस तरह की धारणा शासन के प्रति उत्पन्न हो यह शासन के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए तो यह बात बिलकुल भी ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह नागा लैंड बनाया भी किस तरीके से जा रहा है। नाम इस का नागा लैंड होगा। यह नाम किस आधार पर तय किया गया? वह एक अलग राज्य चाहते थे और हमने अलग राज्य मान लिया। वह नागा लैंड का नाम चाहते थे और हम ने नागा लैंड नाम मान लिया। वह विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत रहना चाहते थे हम ने वह भी मान लिया। हम किसी एक भी बात पर अड़े नहीं। हमें कहीं तो अड़ जाना था कि बस इसके आगे लक्ष्मण रेखा है, इसके पार नहीं जायेंगे और अगर इसके पार जायेंगे तो देश की एकता को विघटन का रावण डस लेगा। यह एक प्रथक नागा होम लैंड की कल्पना एक गलत कल्पना है क्योंकि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक देश है। यह हमारी मातृभूमि है, धर्मभूमि है, कर्मभूमि है और इसमें नागा लैंड और अलग अलग होमलैंड के लिए जगह नहीं हो सकती। हमें उन्हें समझाना चाहिए था और कम से कम हम उन्हें इस बात के लिए तो तैयार कर सकते थे कि यह नागा लैंड विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत न होकर अन्य राज्यों की भांति गृह मंत्रालय के अधीन होगा। किन्तु नागा लोग कहते हैं कि हमें तो भारत में एक ही व्यक्ति पर विश्वास है और वह हैं प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। जहां हम उनके इस विश्वास का स्वागत करते हैं वहां यह अवश्य कहेंगे कि प्रधान मंत्री में विश्वास गृह मंत्री महोदय में अविश्वास तो नहीं बनना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सम्पूर्ण देश में अविश्वास हो और एक व्यक्ति में विश्वास किया जाय।

उस दिन प्रधान मंत्री जी ने लाल किले के अपने भाषण में ठीक ही कहा था कि जवाहरलाल आते हैं और जाते हैं मगर हिन्दुस्तान आता ही है वह जाता नहीं है। उसको जाना भी नहीं चाहिए मगर यह हमारे नागा बंधु देश के साथ अपने को नहीं जोड़ना चाहते बल्कि एक व्यक्ति विशेष के साथ जो अपने को जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें इस बात से विरत किया जाना चाहिए। जब इस देश के शेष पन्द्रह राज्य गृह मंत्रालय

के द्वारा चलाये जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि यह जो सोलहवां राज्य बनने जा रहा है यह क्यों न गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जा सके । मगर नागा लैंड गृह मंत्रालय के अन्तर्गत न होकर विदेश मंत्रालय के अधीन रखा जाना मान कर और उनका एक अलग कांस्टीट्यूशन भी जो मान लिया गया है मैं नहीं समझता कि यह देश की एकता के लिए अच्छा चिह्न है ।

इस मांग का परिणाम यह हुआ है कि जो अन्यान्य राज्यों की मांगें हैं, वे बल पकड़ गई हैं । हमारे देखते देखते भारत की भूमि पर एक मुस्लिम राज्य बन गया । यह नागालैंड एक ईसाई राज्य होगा । हमारे अकाली बन्धु एक सिख राज्य मांग रहे हैं । कल कम्यूनिस्ट पार्टी ने मांग की है कि महा-दिल्ली बनना चाहिए, जो वस्तुतः एक जाट राज्य होगा, जो एक साम्प्रदायिक राज्य होगा । क्या इस देश की एकता टुकड़ों में बंट जायगी ? क्या सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी का इतिहास फिर से दोहराया जायगा ? हमारे नव-निर्माण के काम, हमारे बड़े-बड़े बांध, देश की ग़रीब और शोषित जनता को आर्थिक दृष्टि से प्रगति के पथ पर प्रशस्त करने के सारे कामों पर पानी फिर जायगा, अगर हम देश की एकता की, राष्ट्रीयता की रक्षा नहीं कर सके । मगर यह नागालैंड का निर्माण उस राष्ट्रीयता के शरीर में एक स्थायी कंटक बन जायगा, विघटनकारी मनोवृत्तियों को बढ़ावा देगा । जो अकाली आन्दोलन अपनी मौत मर रहा था, उस में नई जिन्दगी आ गई है और अकाली नेता कहते हैं कि अगर चार लाख नागाओं का एक अलग राज्य बन सकता है, तो चालीस, पचास लाख सिखों का अलग राज्य क्यों नहीं बन सकता है । हमारे प्रधान मंत्री जी भले ही यह कहें कि नागाओं की स्थिति अलग है—और कुछ अंशों में यह ठीक भी है—मगर आम आदमी, गांव में रहने वाला आदमी, जो आर्थिक अभावों से परेशान है और जिसे स्वार्थी नेता विघटन के रास्ते पर ले जाते हैं, इस तर्क को नहीं समझेगा । वह नहीं समझेगा कि लन्दन में एक व्यक्ति बैठा है, जिस की छाया सारे निर्णय पर पड़ी हुई है । वह तो स्वार्थी नेताओं के हाथों में खेलेगा । मेरा निवेदन है कि अभी जो अन्तरिम काल का समझौता किया गया है, इस में जल्दी न की जाये । विधान में संशोधन करने के लिए बिल लाने में शीघ्रता न की जाये । अभी देखा जाये कि जो इन्टेरिम काल है, उस में वहां शान्ति होती है या नहीं । इस का प्रयत्न किया जाये और इस बात के लिए उन्हें तैयार किया जाये वे कि धीरे धीरे देश के साथ एकरस हो जायें, एकरूप हो जायें । धन्यवाद ।

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Statement made by the Prime Minister in Lok Sabha on the 1st August, 1960, regarding the Naga Hills and Tuensang Area, be taken into consideration."

Shri Hem Barua.

Raja Mahendra Pratap (Mathura): My name may also be included in the list.

Shri Hem Barua (Gauhati): Sir, the root cause of the trouble brewing in the Naga Hills on the north-east frontier since independence is the short-sighted policy pursued by our Government. Except for a few differences in the flappings, it is the same policy that was pursued by the British, namely isolation for the Hills that are supposed to be the sentinels of our frontier. The British achieved something because their policy was actuated by a long-range vision calculated to serve their interests, whereas our vision is a result of a pair of myopic eyes, and we do not have that long-range vision. The British instituted walls of separatism between the hills and the plains, through regulations, and nefarious regulations at that. One regulation is

[Shri Hem Barua]

known as the Inner Line Regulation. That was imposed in 1873. There was another regulation subsequently imposed, and that regulation is known as the Frontier Tract Regulation. That was imposed in 1880. Thus, this seed of separatism sown in the Naga Hills ultimately developed, I would rather say, into a banyan tree. It was in 1929 when the British Government briefed the leaders of the Naga people to demand a separate entity for the Naga Hills when the Simon Commission came; and this separatist psychology was engineered by the British. And in the context of freedom we fell a victim to that.

When Prof. Coupland, a British Constitutional expert, visited this country on the eve of freedom, he added fillip to this separatist psychology already existing in those people. He suggested a Crown Colony under the aegis of the British, constituted of the hills of Assam and the hills of Upper Burma joined together. But somehow or other this suggestion of Prof. Coupland did not work, luckily I would say, and when freedom came, freedom came for the whole country,

But it is in the context of this freedom that we missed the bus. We have a responsibility. That responsibility was entailed in us, the responsibility to create and build up a comprehensive Indian mind in the Naga people, so that they might be actuated by the same urges and passions of nationhood in order to serve this nation and this country. But that did not happen, and that is the pity of the whole piece.

And what about the British people? They ruled the Naga Hills for seventy years or so. But they never tried to improve or to change the conditions of the Naga people from the neolithic stage to that of the Twentieth Century. Therefore, when freedom came, it was quite natural that they were enlivened with a passion, a passion to remove their backwardness and at the same time to develop in a way best suited to their genius. I would say that these Naga people are experiencing a new movement of the mind and urge for self-expression and self-determination.

When I speak of this comprehensive Indian mind, one question that is uppermost in my mind is this, whether the creation of this new State called Nagaland is going to reflect the urges and passions of a single nation, whether the creation of of this new State called Nagaland is going to reflect the comprehensive Indian mind or not. If it is going to reflect the comprehensive Indian mind and is going to build up a solid Indian nation with the Naga people as a entity in that pattern, I most wholeheartedly welcome this proposal for the new State.

Now, what about us? Since freedom, instead of trying to obliterate the walls of separatism that were instituted by a foreign power, we tried to maintain them and at the same time reinforce those walls by a few concrete slabs of restrictive orders. No comprehensive Indian mind can grow and develop in a dissipating condition like that. I know, the Prime Minister has a very pet theory. He very often says that these people must be allowed to develop in their own way. That is a right thing to say. At the same time, he says that their way of life is to be preserved, their song, music and all the concomitants. May I quote here from Dr. Verrier Elwin who has also propounded this theory in his admirable book called "Philosophy for NEFA"? But before that may I quote these beautiful words of our Prime Minister? I quote them because of the sheer beauty of the expression. He says:

> "I would rather any day be a nomad in the hills than a member of the Stock Exchange and

listen to that frightful ugly noise. I am quite sure that the civilisation of the tribal folk, of song and dance, will last ultimately when the Stock Exchange will cease to exist in this country and other countries."

May I know, is it in order to prevent the Stock Exchange from making a rude inroad into the Naga Hills, or is it to preserve the civilisation of the Tribal people with their song and dance, or is it, in other words, to preserve the Naga Hills as a paradise for the anthropologists and maintain the people there as museum pieces that this buffer State is created on the, I would say, not too invulnerable frontier which the North-East frontier is? I would like to be enlightened on these points.

If it comes to the preservation of the civilisation of the Tribal people there also you have miserably failed. Modern civilisation is a rude leveller. It has spread its tentacles even on the Naga Hills. This is what Dr. Verrier Elwin, an expert on tribal affairs says about the inroad of modern civilisation into the Naga Hills so far as the Naga boys and girls are concerned:

> "A youth in smart English clothes, and a sola *topi* will not obey his tribal chief who looks so '*jungly*' in his classic attire; girls in meretricious blouses and even trousers, lipsticks on their lips and phoney trinkets in their hair are already showing signs of rebellion against the discipline of society".

Therefore, if your primary motive or purpose was to maintain the civilisation of the Tribal people, there also you have signally failed, I would say.

It is going to be a very small State. But it does not matter, because it is not the size of the State that matters. It is not a major factor. Because there are small States in Europe also. For instance Luxemburg is one. Coming nearer home, we have Bhutan. It is not a big sovereign State. And what about the States that are emerging into sovereign status in Africa? They are not big in size, most of them. Therefore it is not a major factor. But the question is, should we cut a frontier into piecemeal entities like this; should we not have a consolidated entity in the frontier for the sake of our defence? Because, it is an international boundary, hedged in by three foreign countries, China, Burma and Pakistan. I feel, the frontier is always like a football team. As a football team, it has a back line that co-operates into absolute harmony with the centre forward or the front line. Here is the North-east frontier of hills constituting our front line and the plains of Assam constitute the back line of defence. There should be a consolidated and cohesive pattern there so that the team may be a solid team, in order to maintain our solidarity and security. That is not to be found. It has been cut into pieces. What happens? There are dangerous possibilities. For instance, we have carved out from this area N.E.F.A. already. Now comes Naga land. There are other two demands, the demand for a Hill State and a new demand for a S.E.F.A. in the offing. If Assam is cut into pieces like that, this is going to be a dangerous sign for us.

One argument alone can be advanced in favour of this new State. This State is set up in order to quell the storm that Mr. Phizo has raised. I suppose Mr. Phizo can no more flare up any trouble there. Mr. Phizo, after escaping to England, is dead as dodo. I would rather say, Phizo has fizzled out. Whatever that be, whether we had an assurance from Dr. Ao or not, what about the Negotiating Committee appointed by Dr. Ao? That Negotiating committee failed to enlist the approval of the hostile Nagas for this resolution demanding a separate State within the Indian Union. Even at the Kohima conference, where this resolution was adopted, it was greeted by showers of bullets coming from the hostile Nagas. Even then, I would welcome the

[Shri Hem Barua]

new State in view of the fact that I understand the position of the Naga Hills.

It is not only the Naga people who have bled. Our own people, our own boys have also bled. Standing in the cemetery of the war dead, I found a beautiful couplet inscribed on one of the tomb stone. The couplet says:

"When you go home tell them
of us and say.

For their tomorrow we gave our
today."

I think of all our boys who have sacrificed for their country their "today" so that we may have a prosperous and unified "tomorrow". I think of them. When I think that there might be peace, when I think that there may be concord, when I think that a comprehensive Indian mind may be built up, I welcome it most wholeheartedly.

Another thing is very important. They have adopted a resolution. This I could not understand. This is the draft resolution adopted at Mokokchung and it is on the basis of this that they approached our Prime Minister for settlement. The resolution says:

"On reaching the political settlement with the Government of India, the Naga Peoples Convention shall appoint a body to draft the details of the Constitution for Nagaland on the basis of the settlement."

This, I have not understood. Are they going to draft a Constitution according to their aspirations and wishes? Is that Constitution going to be a constitution demanding severance of connection with this country? If that is so, I would say that it is a very dangerous possibility. I am inspired to say like this because when at Kohima, at first, they adopted the resolution, the words, 'within the Indian union' were not there, in the main resolution. When the Governor rang up the Naga Convention people and said that the Governor is not going to meet them on the basis of this resolution, then alone, they added these words 'within the Indian union', and that too in a footnote. It does not constitute a part of the main body of the resolution. Therefore, I have certain apprehensions in relation to this part of the draft proposal. I hope the Prime Minister will very kindly enlighten us on this.

At the same time, after the Kohima Convention, when Dr. Ao came with his comrades to see our Prime Minister, he made a statement at Dum Dum airport. He said like this:

"We shall submit this resolution to the Prime Minister and press for implementation as an interim measure."

I would like to know whether this is going to be an interim measure. If we agree to this part of the draft resolution that they would have the power to draft their own Constitution for Nagaland then, I am apprehensive of that also.

About revenue, it is said that it is going to be very poor, because the only source of revenue for Nagaland is Forest. The forests yield an annual income of Rs. 3 lakhs. In 1956, they yielded a lamentable sum of Rs. 20,000. Therefore it is going to be perpetually a non-viable State economically. That is true. What of that? We have been heavily subsidising this area. We propose to subsidise Rs. 4 crores for the development of this area. When we take into account other things, this is not a big sum. I would say that attempts should be made to discover deeper sources of revenue if that is allowable under the Constitution or the Constitution that is proposed to be drafted. In that case, I leave the matter to Sardar Swaran Singh and Shri K. D. Malaviya. They can help.

About the name Nagaland, there is a controversy that it is not an Indian name. But, then, we have

accepted so many new names in our country, so many words that are not of Indian origin. We have adopted the word Congress. It has gone deep into the psychology of the people due to the struggles that we had raised for freedom under its auspices. The Nagas have also had struggles. This word Nagaland has gone deep into the psychology of the people and it is very difficult to wipe it out. Call a rose by any other name, it will smell as sweet. Call the Nagaland by any other name, it will smell as Nagaland and nothing else.

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): Mr . Speaker, the sixteenth State of the Indian Union has come into being and we welcome the formation of this sixteenth State, Nagaland. We hope that this small area in India, which has been torn by strife, which has really suffered deeply, and which, in many ways has been a troublespot and a scar on the face of India, at last, will have peace and the Nagas will be able to work out their destiny in conformity with Indian traditions and also will be a source of strength to the rest of India.

When we discuss Nagaland, we cannot forget the background of this area. Even in the days of British rule, these proud Nagas had fought many a battle against the British. I am told there were as many as 10 expeditions against them. Down from 1835 to 1851, the urge for freedom of the Nagas was a well known fact. After that, we know how the British ruled in this area. They had what was known as the Inner Line. Actually this area, comprising the Khazi Hills, Lushai Hills as well as the Naga Hills, was formed into an isolated area known as frontier tracts and it was administered by the Governor. Funds were made available by the Ministry, but the Ministry had no administrative power. This was the background. The only people who were allowed were the missionaries. The missionaries did play a very important part in this area.

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch. Tribes): And the banias.

Shrimati Renu Chakravartty: In those days, even the banias were not allowed.

Shri Jaipal Singh: They were allowed.

Shrimati Renu Chakravartty: It was chiefly the missionaries that were the dominating factor in those days. May be because of that, this area is a Christian area. We do not raise the question of religion. But, we do realise that having this background, the missionaries have played a very important part not only socially but politically also. We do know, at least those of us who come from this part of India know, how only a few years ago one of the Welsh missionaries in Jorhat was externed from India because it was reported that they had certain political activities in this area. This factor is also there. Mr. Phizo has very mysteriously gone over to England and he is now under the patronage of a missionary—no doubt a distinguished person who has fought for the rights of the coloured people in South Africa. This Mr. Michael Scot has taken Mr. Phizo under his patronage. These are pointers that the influence of the missionaries still remains. We have to be vigilant about this. Now that this particular area of India is being given the fullest autonomy within the Indian Union to develop itself, we hope the integration of this area with India will be assured and that they will march forward and become a source of strength to the Indian Union.

It does seem to me that the decision which is being taken today could have been taken a little earlier. The Prime Minister may correct me, but I think that the composition of the present Naga delegation is more or less the same as that of the one that came 1½ or two years ago, and their demands were also more or less the same. The point of dispute all along

[Shrimati Renu Chakravartty]

had been that the people who claimed to represent this area had been demanding an independent State, and naturally nobody, no party in India, could accept it. It was only when they accepted the position that they would be satisfied with the fullest autonomy within the Indian Union that we could accept their demand, because, as the Prime Minister has rightly pointed out, the policy of the Indian Union has been to grant the fullest autonomy to the tribals so that they may be able to develop on the lines of their own choice.

The first convention of the Naga people took place in Kohima in 1957 as a result of which the Government of India took the decision that there should be a single administered unit constituting the Naga Hills of Assam and the Tuensang Frontier Division of NEFA under the External Affairs Ministry administered by the Government of Assam. That was more or less the demand and that was conceded. Even after that things did not work out the way everybody had hoped they would, and in 1958 at the Ungma convention a liaison committee was set up to see if some understanding could be reached with the underground Nagas. Then also things did not go very well, and it was only at the Mokokchang convention of October, 1959 that the 16-point memorandum was passed and thereafter the Naga delegation came here. We are glad that at last the Naga people have accepted that they are a part of the Indian Union, and that within the Indian Union with the fullest autonomy guaranteed to them, they will form their own State under the Governor and under the External Affairs Ministry. I have no doubt that their being under the External Affairs is not a pointer that they would want to secede the very next moment. After all, the NEFA area has been under the External Affairs Ministry so long, and so this need not necessarily give rise to the suspicions which have been raised by my hon. friend Shri Vajpayee. But it is true the question of the transitional period remains. How long is it going to be? As far as I can make out, the memorandum of the convention had mentioned a period of ten years. That, I think, is far too long a period to be regarded as transitional, and I hope much earlier than that the Naga people will be able to have their own elected representatives.

It is said the Naga convention would appoint a body to draft the details of the constitutional changes. What exactly does it mean? We take it that with the largest amount of freedom granted to them, they will remain a part of the Indian Union and be under the same Constitution. So, what exactly does this drafting of the constitution mean? I think that will be explained by the Prime Minister.

Naga Land undoubtedly has a small population, it being only 360,000, and it has only a small area of about 6,000 square miles and 700 villages, but we have to realise that today there are areas in our country which, because of certain historical developments and certain social and cultural developments, demand that they should be recognised as separate entities within the Union. For example, there have been big movements going on in Manipur and Tripura. Tripura also has only six to nine lakhs of people, and Manipur has only a small area, but we have recognised that they do have distinct features. They demand the right of self-expression politically, economically and culturally. That is why, now that we have accepted the demand for Naga Land,—it is a wise decision and the only decision to be taken in the circumstances—the demand for responsible government of the people of Manipur and Tripura can no longer be put off. Once Naga Land with its elected representatives comes into being, it is only natural that the people

of Manipur and Tripura should also be guaranteed elected representatives and a legislature.

We wish the sixteenth State of Naga Land all the best, we welcome it and fervently hope that our brothers there will be able to build their own future and develop themselves in such a way as to bring strength to India. I am sure all parties in Parliament will continue to support their just rights, and that generous financial aid will be made available to them so that this area which up till now has been a trouble spot, so to say, will be able to become a source of strength and prosperity for the Indian people and the Indian Union.

Mr. Speaker: A number of hon. Members want to speak. I will allow ten minutes. Pandit Brij Narayan "Brijesh".

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश (शिवपुरी): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करने के लिए हमने जैसा शान्तिपूर्वक और सुसंस्कृत रूप में संघर्ष किया, न तो संसार ने ही उसको आदर्श रूप में लिया और न हमारे देशवासियों ने ही लिया ।

मुझे इस सम्बन्ध में उस पृष्ठभूमि की तरफ अपने सदन का ध्यान आकर्षित करना है, जिस सिद्धान्त को लेकर हम अब तक चल रहे हैं, जिस प्रकार हमने संसार के सामने अभी तक भाईचारे का प्रचार किया है और हमने सारे संसार को विश्वबन्धुत्व के आधार पर एक जगह एकत्रित करने की चेष्टा की है, उसके होते हुए भी यह दुर्भाग्य है कि हिन्दू मुसलिम भाई भाई बोलते बोलते पाकिस्तान बन गया । हमको कहा गया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा परन्तु वह बन गया । और आज हम देखते हैं कि उसके बनने का सुपरिणाम न पाकिस्तान को ही मिल रहा है और न हिन्दुस्तान को ही मिल रहा है । वह भी दुखी है और हम भी दुखी हैं और रोज संघर्ष चलता है, रोज लड़ाई चलती है । ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान बन जाने के बाद हम ने फिर प्रयत्न किया, अपने सैकुलर राज्य के आधार पर सब को एक साथ एकत्र करने का परन्तु मुझ दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सब ने प्रम के साथ रहने के बजाय भीतर ही भीतर अपनी कूटनीति का कुचक्र इस हिन्दुस्तान में चलाना आरम्भ किया । मैं देखता हूं कि प्रशंसा तो बहुत की जाती है कि ईसाई मिशनरीज़ ने बड़ा काम किया लेकिन मिशनरीज़ अगर भ्रातृत्व की भावना से ही केवल कार्य कर रहे होते तो सम्भवतः मुझे विरोध करने का अवसर नहीं मिलता लेकिन वे अपने निहित राजनैतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिये हिन्दुओं को धीरे धीरे ईसाई मजहब में बदल रहे हैं और इस देश की जो राष्ट्रीयता है इस देश के प्रति जो भक्ति होनी चाहिये थी उस को विदेशों की तरफ वे इस प्रकार से ले जा रहे हैं और धीरे धीरे इस देश को वे खंड खंड करते जा रहे हैं । हमारा राज्य और हमारा शासन इस तथाकथित भ्रातृत्व की भावना से दब कर इस प्रकार की अनुचित मांगों को स्वीकार करता चला जा रहा है और मैं समझता हूं कि उन को स्वीकार करने का परिणाम यह नागा राज्य है । यदि देशभक्ति की भावना से वहां विद्रोह खड़ा हुआ था तब तो हमें उन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिये था । जैसे ही उन्हों ने विद्रोह किया था वैसे ही हमें यह नागा राज्य स्वीकार कर लेना चाहिये था । नागाओं को हमें वह स्वतंत्रता और सत्ता दे देनी चाहिये थी जिसे कि वह मांगते थे परन्तु ऐसा प्रतीत होता है और हम को स्वयं ऐसा मालूम होता था कि यह नागा राज्य बनाने में इस देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायगी । नागा राज्य को स्वतंत्र करने में कोई लाभ नहीं होगा, इसेलिये हम ने विद्रोह का दमन करने की चेष्टा की परन्तु उस का परिणाम यह हुआ कि वह दमन तो हुआ नहीं और वहां विद्रोह

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

पैदा करने वाले जो महान नेता थे फिजो साहब वह किसी प्रकार से यहां से भाग निकले और भाग कर इंगलड में पहुंच कर हिन्दुस्तान के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं । हिन्दुस्तान के विरुद्ध प्रचार करने का उन को एक ऐसा सुन्दर स्थान मिल गया जिस से संसार भर में भारतवर्ष के विरुद्ध एक वायुमंडल का निर्माण कर सकें । जहां भारतवर्ष विश्व के वायुमंडल को शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है वहां भारतवर्ष में से ही हमारा एक भाई हमारी अयोग्यता और असावधानी के कारण निकल कर हमारे विरुद्ध वायुमंडल का निर्माण कर रहा है । यह कैसी विचित्र बात है कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि वह इंगलैंड वाले नहीं चाहते कि वहां इस प्रकार का वह भारत वरोधी प्रचार करें । मैं समझता हूं कि भीतर ही भीतर उस को प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि वह इस तरह का भारत विरोधी प्रचार करते रहें और यह कैसी विचित्र बात है कि यह जो डिप्लोमेसी है यह जो कूटनीति है उस को उदारता के नाम पर दबाया न जा सके और हम उदारता बर्तते चले जायें और दूसरे हमारे साथी कूट-नीतिक चालें चलते चले जायें, यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

जैसे मैं ने आरम्भ में कहा कि यह जो नागा लैंड और नागा राज्य स्वीकार कर लिया गया तो अब इस के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मैं इतना अवश्य पूछना चाहूंगा कि बुद्धिमत्ता के आधार पर यदि नागा राज्य एक अलग राज्य बन सकता है तो हिमालय से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक क्या एक हिन्दू राज्य नहीं बन सकता है ? इस भारतवर्ष देश में जितने भी निवासी बसते हैं वे सब के सब वास्तव में हिन्दू हैं । अब आज जो अपने आप को ईसाई कहते हैं आखिर वह भी तो हमारा अपना ही रक्त है । वे भी तो इसी भारतवर्ष देश के रहने वाले हैं और उन्हें अपने आप को हिन्दू कहने में क्यों आपत्ति होनी चाहिये ? मैं ने एक बार निवेदन किया था कि यहां जो मुसलमान हैं वे भी तो हिन्दू ही हैं । वे कोई दूसरे हैं क्या ? अब जैसे हमारे देश में रामानुज आचार्य, वल्लभाचार्य और शंकरा-चार्य आदि संत और महापुरुष हुए हैं और उन के शिष्य सब हिन्दू हैं उसी प्रकार ईसा मसीह और मुहम्मद आदि के भी शिष्य हिन्दू ही हैं और फिर उन्हें अपने आप को हिन्दू कहने में क्यों आपत्ति होनी चाहिये । मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रीयता और हिन्दुत्व की भावना से यदि देश को एक सूत्र में आबद्ध किया जाय तो यह आज जो नागा राज्य, सिक्ख राज्य कायम करने की मांग उठ रही है वह नहीं उठेंगी क्योंकि याद रखिये कि अगर यह विघटन का क्रम रुका नहीं और जारी रहा तो फिर मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है बल्कि ब्राह्मण राज्य, क्षत्री राज्य और वैश्य राज्य ** ** कायम करने की मांग का भी हमें सामना करना होगा और यह हमारा देश विघटित होता चला जायगा ।

नागा लोग मेजारिटी में नहीं हैं । मेरा निवेदन यह है कि देश के इस तरह से खंड खंड कब तक होते रहेंगे । इस प्रकार से देश कब तक विभाजित होता रहेगा ? जब एक की पृथक राज्य स्थापित करने की मांग स्वीकार कर ली जाती है तो दूसरे को उस से प्रेरणा मिलती है और वह खड़ा हो कर मांग करने लग जाता है कि हम को भी एक अलग राज्य मिलना चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि यहपृथकत्व की भावना अच्छी नहीं है और यह देश के हित में नहीं है । यह बड़े खेद की बात है कि इस प्रकार की विघटन की यह प्रवृत्ति देश में इधर उधर ज़ोर पकड़ती चली जा रही है

**Expunged as ordered by the Chair.

और दूसरी ओर हम दूसरों को भाई बनाने की चेष्टा करते हैं । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज जहां हमारे देश की सुरक्षा को खतरा महसूस हो रहा है और हमारी सरहदों पर आक्रमण हो रहे हैं वहां एक अलग राज्य बनाने का आन्दोलन चल रहा है । सिक्ख राज्य मिलना चाहिये ऐसी मांग उठाई जा रही है । पंजाबी सूबा स्थापित करने के वास्ते आंदोलन चल रहा है । इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस तरह उन को भी पंजाबी सूबा मिलना चाहिये और यह नागा राज्य के निर्माण होने से पंजाब के गांव गांव में इस प्रकार का प्रचार प्रारम्भ हो जायगा कि पंजाबी सूबा बनना चाहिये और इस नागा राज्य को स्वीकार कर लेने से पंजाबी सूबा बनाने की मांग अत्यन्त निकट पहुंच गई है क्योंकि सिक्ख देख रहे हैं कि नागाओं ने विद्रोह कर के अपना एक अलग राज्य ले लिया तो वे भी क्यों नहीं ले सकते । इतना ही नहीं मुझे तो यह भी भय प्रतीत होता है कि अभी तो केवल इस के लिये सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा है लेकिन अगर कहीं और उन को भड़काया गया तो हो सकता है कि जैसे नागाओं ने उत्पात किया वे भी कोई उत्पात न कर बैठें और जैसे वहां हमारी सेनाओं को जा कर कार्य करना पड़ा कहीं वैसी ही भयानक स्थिति यहां पर भी उत्पन्न न हो जाय । सरकार को समय रहते चेतना होगा क्योंकि ऐसी जगह जहां पर कि हमारे देश की सीमायें लगती हैं इस तरह का एक असन्तोष और गड़बड़ होना कदापि उचित न होगा । जिस तरह से नागा हिन्दू हैं उसी तरह से सिक्ख भी हिन्दू हैं और जैसे नागाओं को और शेष लोगों को आपस में लड़ाया गया वैसे ही आज सिक्खों को जोकि हिन्दू हैं अन्य हिन्दुओं के विरुद्ध उभाड़ने की साजिश चल रही है । यह सारी लड़ाई हिन्दू राष्ट्र के भीतर ही हो रही है । इस को बाहरी लोग अपनी कूटनीति का कुचक्र फैला कर चलाया करते है । विदेशी लोग यहां आ कर और अपने फिफथ कौलमिनिस्ट्स घुसेड़ कर इन को भड़काने की चेष्टा करते हैं और हमारे राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं । यह बड़े दुःख का विषय है कि जो डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं और जो अपने आप को प्रजातांत्रिक मानते हैं, वे उस के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं । जो प्रजातांत्रिक अपने को मानते हैं वे यहां प्रजातंत्र राज्य को सफल नहीं होने देना चाहते । वे लोग जोकि संसार के सामने आदर्श प्रजातंत्र देना चाहते हैं और जोकि प्रजातंत्र के हामी हैं जब वे ही हमारे प्रजातंत्र को बिगाड़ने का कुचक्र करते हैं तो इस बात के लिये उन्हें गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि कम से कम उन को तो हमारे इस मार्ग में और जबकि वे हमारे ही विचारों के हैं, बाधक नहीं बनना चाहिये लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश के ही एक निवासी श्री फिज़ो इंगलैंड में विराजमान हैं और वे वहां पर भारत विरोधी प्रचार करने में संलग्न हैं । लेकिन यह सब को याद रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र समाप्त हो जायगा तो इंगलैंड का प्रजातंत्र भी बच नहीं सकता है । उन्हें भी समझना चाहिये कि प्रजातंत्र यदि भारत में रहेगा तो संसार में भी रहेगा और यदि भारतवर्ष में प्रजातंत्र समाप्त हो जायगा तो संसार में भी प्रजातंत्र समाप्त हो जायगा और उस हालत में संसार में भी प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकेगा । इसलिये इस प्रकार का कुचक्र बाहर चलने नहीं देना चाहिये । मेरा तो भारत सरकार से निवेदन होगा कि वह फिज़ो महोदय जोकि यहां से चले गये हैं उन को बुला कर इस प्रकार का अपराध करने वालों को दंडित करना ही चाहिये ।

यह नागा राज्य तो अभी निर्माण हुआ ही नहीं है । प्रधान मंत्री महोदय ने केवल वक्तव्य ही दिया है । उन के नेता यहां आये थे और उन के साथ बातचीत हुई और इस समस्या पर गौर किया गया है । शान्ति बनाये रखना तो परमावश्यक है परन्तु इस

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

प्रकार की शान्ति जिससे कि और अधिक अशान्ति पैदा हो, इस प्रकार की सद्भावना जिससे और अधिक असद्भावना पैदा हो और इस तरह का भ्रातृत्व जिस से कि शत्रुता को अधिक बल मिले, वांछनीय नहीं और इस को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। हमें वास्तविकतावादी बनना चाहिये। हमें रियालिटी के साथ वास्तविकता के साथ सामने आना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो नागा राज्य का निर्माण किया गया है और इस को नागा लैंड का नाम दिया गया है यदि हम ने सतर्कता नहीं बर्ती तो हो सकता है कि कल को यह नागा लोग कहने लगें कि हम को तो यह नागा राज्य एक स्वतंत्र राज्य ही मिला है और जैसीकि संविधान में व्यवस्था है शेष राज्यों की भांति इन लोगों ने गृह मंत्रालय के अन्तर्गत न रह कर अपने को विदेश मंत्रालय के साथ रक्खा है। अब नागा लोगों ने कहा कि वे होम मिनिस्ट्री के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। अलबत्ता विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। अब मेरा कहना है कि यह विशेष फर्क उन के साथ क्यों किया गया। और उन को एक अलग दर्जा शेष राज्यों के मुकाबले क्यों दिया गया। वह नागा राज्य ठीक जैसेकि हमारे दूसरे पन्द्रह राज्य हैं उसी प्रकार यह सोलहवां राज्य होना चाहिये था और इस को भी गृह मंत्रालय के अन्तर्गत रहना चाहिये था। उस को भी समूचे देश के साथ संगठित हो कर चलना चाहिये। इस प्रकार का उसे एक अलग दर्जा देना यह देश के लिये घातक है। मैं प्रधान मंत्री जी से चाहूंगा कि वे कृपा कर के इस बात को स्पष्ट करें कि आखिर कब तक देश के इस प्रकार से खंड खंड होते रहेंगे ? अगर यही विघटन का सिलसिला जारी रहने दिया तो फिर कल को किसी दूसरे प्रान्त की मांग आ जायगी और परसों किसी अन्य राज्य को स्थापित करने की मांग आ जायगी। हम को समय रहते आज की बिगड़ती हुई परिस्थिति पर काबू पाना होगा और हम को स्वयं अपने विचारों के अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिये। दूसरे की परिस्थितियों से बाध्य हो कर अपने सिद्धांतों के विपरीत हम को नहीं जाना चाहिये।

अन्त में मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह नागा राज्य का निर्माण न किया जाय और उन को प्रेम के साथ इसी देश में मिला कर चलाया जाय। इतना छोटा सा प्रान्त बनाने से न उन की आर्थिक समस्या हल होगी और न कोई दूसरी समस्यायें हल हो सकेंगी। इतना ही निवेदन कर के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

16 hrs.

Shri Jaipal Singh: I am glad to be able to participate in this interim debate. I consider that this is only an interim debate. I would like my hon. friend from Assam, Shri Hem Barua, to remember all that he said this afternoon, when the debate on Assam comes up. I hope he will rise to the same heights when there is the debate on Assam here. Sir, I do not want to explode by any theocratic emotions as seems to have been done by some of my friends who have preceded me. We are deliberately and definitely in a secular State. And, other emotions that are dragged into it, to me appear, on a very special occasion like this, to be completely out of place.

I think the country should congratulate the Prime Minister not because he has done something right. We do not know yet whether this will prove to be the right thing. I am prepared to make that concession. But, I think it has required tremendous courage for him to defy his own party, to defy the entire country in deviating from what has been the written law in regard to the formation of States hitherto.

Hitherto we have gone on the principles of viability, linguisticism, which has been the curse of this country, and various other factors. Arguments have been brought in about the small number of Nagasthanis —that would please some of my friends, they do not like this foreign sounding Nagaland. Perhaps, I can suggest something more Sanskritic, Naga Giri, that will please them although it may not reconcile them.

An Hon. Member: Naga Pradesh.

Shri Jaipal Singh: But, perhaps, my hon. friends forget that there are quite a few States which we have—they may not be independent States—in Assam itself. What is the position of Manipur? What is the position of Tripura?

In the past in British India—we seem to invoke our abuse on the British whenever it suits us—there were definite reasons—which some of us forget—why they pursued a certain pattern for the formation of States. We had admirable States like Coorg. I do not think Coorg is better off today in the new dispensation. We have been told and we are being told year in and year out, times galore, about the missionaries. I wish my friends would go to the Naga Hills for themselves; and not be academic from a distance. I wonder how many of them have been there. I often wonder. I am not one who is going to glorify the unfair proselytisation that has taken place in the past. But these were areas, particularly the tribal areas, where health, medicine, education and the like were taken by the missionaries. And, for the matter of that, believe me, we would not have had independence as early as we have done but for the education that was given in this country by foreigners—call them missionaries or what you will. Whatever has happened in those tracts is due to the fact that my friends who today talk loud did nothing for those areas. They like to call it Hindustan or Hindistan. Do they know their jobs? Have they been to these areas? Do they really know the problems that our Prime Minister has had to face?

Nearly ten years ago, I was the first one to appeal to the Prime Minister of India to meet Mr. Phizo in Delhi. When he was in Assam, the Assam administration saw to it that Mr. Phizo, "the rebel, the murderer" was not allowed to get anywhere near him in Shillong. He followed him to Calcutta. And the same picture. He was not allowed to get near him. He was wandering about in Delhi, this capital city and, fortunately, the Prime Minister was good enough to permit me to take him to his house. Then, after that talk, impressed as he was, for a while he withdrew the rebellion and revolution. But, unfortunately, after that he went out of his mind. That is, I think, the most uncharitable way I can put it. But, at any rate, in this debate, Mr. Speaker I do not think it is necessary for us to bring in Mr. Phizo. He is a personality of the past. He no longer cuts any ice. The sooner we deal with the people who are actually there and who are willing to talk to us the better. That is the important point.

I am not concerned with the size, the population or the financial implications of this new State: call it a State, call it anything else. The question is, what solution have our friends to offer, those who are critical, apart from the fact, it is a frontier State? I am not concerned whether it is a frontier State or not. Supposing it were not a frontier State and the same situation persisted? I would like to know whether they have any solution to offer. They have themselves made no effort to get near our fellow-citizens to bring them round to the thought of abandoning this separation idea; and it is absolutely wrong.

I think, I know more than most people—I think, I know as much and, perhaps, more than the Prime Minister of India—I think the false charges

[Shri Jaipal Singh]

that have been made in this House—and sometimes by the Prime Minister himself also—have not had all that foundation behind them that they wanted to get out of India. Let us not quote what the foreigners say about them. Till very recently, it was very difficult for us to get near them at all. It is only a very recent pricture that we have been able, as it were, to have a round Table Conference with them to talk and find out what they wanted. As far as I am concerned, at no stage did they ever want to sever their connection from the Union of India. It was only because we took to punitive measures that they were forced into that situation.

So, let us remember that this is only an interim step. What the consequences will be will depend upon the attitude we develop—whether we are sincere about it. Because my friend Shri Hem Barua will warn this House as he will when the other debate comes about the other five hills. What next? He will warn you about Jharkhand. He will say, what next. He will warn you about something else—what they call fissiparous.

I was one of the people who collected signatures when the question of Greater Bombay State came in this very House. Why did we do it? Because, at that particular juncture, there seemed to be no other solution whatever. And, I really congratulate the hon. Prime Minister of India for having shown pluck and courage in defying the whole country, the general sentiments, in meeting the mere 4 or 5 lakhs of people and trying to solve the problem. It is no good quoting Dr. Verrier Elwin. I can also quote so many sentences from his previous speeches. Dr. Verrier Elwin is not the same man today as he was 30 years ago. Let us remember that. Only yesterday he has become an Indian. He is more Indian now than Shri Hem Barua. He is more tribal now than Jaipal Singh. He is an authority. . . .

Shri Hem Barua: May I be permitted to say, Sir, that the hon Prime Minister has written a foreword to his book called, *The Philosophy for NEFA*, and that is why I am interested. I am one of his admirers.

Shri Jaipal Singh: I am very glad the Prime Minister is willing to learn every day. Read the Prime Minister's utterances. Only yesterday they were slightly different. He is willing to learn every day. Essentially his heart is in the right direction. That is what matters.

So, what I have to submit is that the argument that might be adduced as a parallel, as an analogy affecting other States, does not apply here at all. This is a very special problem. Let us not connect this with the frontier traits because there is the Chinese aggression. It is a human problem; essentially and basically it is a human problem. We have had to admit that in the past we have made mistakes. And, this is, to my mind, for the time being an interim settlement; because I am not prepared to agree with the Prime Minister that it is a permanent solution. I say, as an interim step, there is nothing better that could have been done. I personally congratulate the Prime Minister for the courage he has shown. I hope he will continue to show courage in regard to other problems also.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri (Berhampore): Mr. Speaker, Sir, I unhesitatingly welcome the formation or the decision for the formation of Nagaland as a separate State, the 16th State of the Indian Union, because, primarily, it shows a recognition of the fact that the uniform pattern that we had prescribed for our political life will have to be revised in order to give full scope to the realisation of the distinct personalities of the various communities that live within the comprehensive unity, that is, the Indian Union. Observations have been made here that the Naga

people were fighting with our Government because the missionaries were sent there by the Britishers and imperialists and so they had developed a separatist tendency. Historically that is not borne out by facts. As early as June 1946, the Naga National Council—there was a Naga National Council even then—passed a resolution expressing its approval of the scheme proposed by the Cabinet Mission in the State Paper of May 16. 1946 and their desire to form part of Assam and India. The resolution also protested against the proposal to group Assam with Bengal. According to the Cabinet Mission scheme, Bengal and Assam and all those areas which were Muslim majority areas would have been grouped together and this was a protest against it. That shows that the Naga people in their own way tried to take part and contribute in the formation of the emerging independent State of India.

I need not go over the subsequent history when many unpleasant things have happened. Even though it is after 13 years, I can only welcome the fact that even belatedly this decision has come to be taken. We should never forget that the political pattern that we have set for ourselves may not be adequate to give expression for the distinct personalities and the individualities of the different communities that go to make India. In the Constituent Assembly a sub-Committee was appointed to go into this question and it makes special reference to the hill areas in the North-eastern region of the country. While emphasising that the tribal institutions and tribal professions of these people should survive they also observed that there should be a larger unity of India. That is what they say:

> "For this, there must be a larger unity, and the question which arises is whether that unity should be a unity of the hills only or a unity with the plains. The distinctness of the hill peoples constitutes a strong argument for the former. There is no provincial boundary in India so sharp as the line that divides the hills from the plains of Assam. The peoples who live on either side of every provincial boundary have closer ethnological, historical and cultural affinities than the peoples on either side of this line."

The decision for the formation of the Nagaland naturally has within itself larger implications over which we should ponder. Other claims have been put forward. The demand for the formation of the hill States in Assam has come up and I think it will also soon become irresistible.

The only thing in this connection that is intriguing me is the question about the constitution-making power of the new State. Some statement has been made by the spokesman of the Naga people that the new State will have the constitution-making powers and I do not know what would be the Government explanation as to that. I have tried to find out as much guidance as I could from the statement made by the Prime Minister on the 1st of August where he refers to a "transitional period during which an interim body will be constituted with representatives from each Naga Tribe to assist and advise the Governor in the administration of Nagaland". This council would be composed of representatives from each Naga tribe. Will it constitute a cabinet or some kind of legislature? That is not very clear. It is said that special responsibility of law and order, so long as the situation continues to remain disturbed, will vest in the Governor and the Governor will also have special financial responsibility in the interim period. But after the interim period, what will be the position? The Prime Minister stated that there would be a legislative assembly to which a council of Ministers will be responsible. That is like any other State. We have also to recognise the fact that in that area with so small a population, the delimitation of constituencies and the basis of representation will all have to be changed.

[Shri Tridib Kumar Chaudhuri]

There is also reference in the Prime Minister's statement about the safeguards provided in the Sixth Schedule of he Constitution. It makes no special reference to the administration of the tribal districts or divisions of Assam to which the Sixth Schedule relates. When the Nagaland forms a full-fledged State, will these provisions of the Sixth Schedule be incorporated in the Constitution of the new State also? All these things will have to be clarified. As I see it, there is no harm in allowing these people even to form their own Constitution.....

Shri Tyagi: That is constitutionally impossible. No State is permitted to do that.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: The Constitution can also be changed; you have done it eight times. Power also can be given to the people of the new State. Kashmir was given that power. I do not want to lengthen this part of my speech. I only wanted to draw the attention of the House to the fact that a special constitution for Nagaland will become an inevitability and because we want to grant that power of autonomy, they will have to be consulted and their opinions will have to be given due recognition, that is to say, eventually constitution-making powers will have to be given to them.

I would only say that it is time that we give our very serious consideration to all these aspects of the question. Nagaland is going to be the 16th State and we wish God-speed to it. But other communities within the body-politic also have their own demands and these demands will have to be taken into account. It is clear in Tripura and Manipur and other places we shall have to evolve multiform patterns of autonomy for our entire State edifice.

राजा महेन्द्र प्रताप : स्पीकर साहब, मैं इस प्रश्न को बहुत ही महत्व देता हूं । आज मेरे चार दांत निकाले गये, मुख से खून भी गया है, मगर तो भी मैं यहां आया हूं इस विषय पर बोलने के लिये ।

मुझे बड़ा दुःख हुआ यह सुन कर कि हमारे पंडित वाजपेयी जी कुछ कुछ ऐसी बातें कह गये जिन से कि यहां पर बजाय इस के कि हम नजदीक आयें हमारे मन और दूर हो गये । सोचना चाहिय आप को पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, कि आया आप दूसरों को मित्र बनाते हैं या अपने से जुदा करते हैं आप ने देखा कि कम्युनिस्टों ने क्या किया । कम्युनिस्टों ने कहा कि पंजाब का सूबा बनाना चाहिये ।

Mr. Speaker: The hon. Member may kindly address the Chair.

राजा महेन्द्र प्रताप : निवेदन यह है कि आप से कम्युनिस्टों ने बाजी मार ली । कम्युनिस्टों ने ज्यादा मित्र बना लिये पंजाब में और यहां पर दिल्ली के चारों तरफ । मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण जो पीछे हटे हैं, उन को और पीछे न हटाइये ।

मैं ब्रज से आता हूं । मुझे कहा जाता है कि मैं ब्राह्मण और गौ का रक्षक हूं । तो मैं आप से अर्ज करूंगा कि ब्राह्मणों के लिये इस समय यह बड़ा भारी प्रश्न है कि कैसे देश वासियों से और समस्त संसार से मित्रता गांठें । मुझे संस्कृत तो नही आती लेकिन संस्कृत में कहा जाता है कि समस्त ब्रह्मांड को भाई बनाओ । जब आप नागालैंड कहते हैं तो मानो आप नागाओं से नफरत करते हैं । हम को एक बड़े सिद्धान्त पर काम करना चाहिये । हमारे प्रधान मंत्री जी कृपा कर के बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नागा भी हम से प्रसन्न हों । अब तो कृपा कर के वह पाकिस्तान भी जा रहे हैं जो मैं उन से बार बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तान से मित्रता करनी चाहिये । मैं तो कहता हूं कि आर्यान बनाइये, ईरान से आसाम

तक और हिमालय से सीलोन तक । फिर आपस में कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा ।

इस में कोई हर्ज नहीं कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य रहें । अंग्रेजों के समय में ५६३ राजे या महाराजे थे तो क्या हर्ज हुआ था ? मैं ब्रज से आता हूं । मैं भागवत की कहता हूं कि श्रीकृष्ण का था द्वारिका में, छोटा सा राज्य था और रामचन्द्र जी का अयोध्या का राज्य । नागालैंड से भी छोटा था । इतिहास हमें बतलाता है कि छोटे छोटे राज्य थे और आज भी छोटे राज्य हैं । जोर्डन क्या है ? आप नक्शे पर देखें । जोर्डन एक छोटा सा देश है । यमन एक छोटा सा देश है । मगर उन के नुमायन्दे न्यूयार्क में बैठे हैं । तो यह बात उठाना बेकार है कि यह थोड़े से लोग हैं या छोटे से इलाके के लोग हैं । ये गलत बातें हैं । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि एक आदमी दूसरे आदमी से सिया नहीं जा सकता । अनेक कुटुम्ब रहेंगे । अनेक जातियां रहेंगी । उसी तरह से मुल्क भी रहेंगे मगर वह गुथे रहने चाहियें । मैं माननीय पंडित जी से विनयपूर्वक अर्ज करूंगा कि मेहरबानी कर के पंजाबी सूबा भी जल्दी से जल्दी बना दीजिये और मैं तो अर्ज करता हूं कि अगर मेरे तरीके से पंजाब में काम हो, खत्री संघ बनते, जट्ट संघ बते और ऐसे संघ बनें जिन में हिन्दू और सिख दोनों हों, तो हिन्दू और सिखों के अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा । और इसी तरह से हिमाचल भी बनाइये, काश्मीर से तेपाल तक और हमारा ब्रज भी बनाइये, मथुरा वृन्दावन का । मैथिल और झारखंड बनाइये । मैं तो कहता हूं कि नागपुर का अलग राज्य भी बनाइये श्री अणु जी का ।

मैं तो पूरा समर्थक हूं नागालैंड का और मैं पूरा समर्थक हूं छोटे छोटे राज्यों का । प्रत्येक स्थान स्वतंत्र हो मगर सब गुथे रहें एक संसार संघ राज्य में ।

Shri P. K. Deo (Kalahandi): Mr. Speaker, Sir....

Mr. Speaker: I would request hon. Members to confine their remarks to five minutes.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): Sir, the time may be extended.

Mr. Speaker: It will be extended if necessary.

Shri P. K. Deo: Mr. Speaker, Sir, I sincerely desire that the settlement reached by the Government of India with the Naga representatives will be a permanent solution of the problem and it will lead to the emotional integration of that area with the rest of India. In the present context, I think this was the only solution possible, and therefore it was more a decision of administrative convenience.

But Sir, the statement of the Prime Minister raises certain pertinent questions. They are (1) the viability of that area, (2) the manner in which the Nagas got the Naga Land (3) does it solve the Naga problem and (4) why the External Affairs Ministry would be looking after this area.

So far as the question of viability is concerned, the previous speakers have already pointed out their grave doubts. Sir, as soon as we concede this Nagaland, I am sure there would be demands for Vidarbha or Mithila or for the Punjabi Suba—my hon. friend Shri Jaipal Singh started dreaming about Jharkhand also.

Shri Jaipal Singh: Dreaming only.

Shri P. K. Deo: I feel that the cir, cumstances in which this decision has been taken by the Government give this impression in the minds of the people that the Government is going to yield to force and it takes away all the good grace of it. I think this is a very bad tendency. If the Government sincerely felt for a Nagaland, then they should have created this Nagaland when a few years back this House passed the Bill for the creation of the Naga Hills and the Tuensang Area. I personally feel that the ideal solution would have

[Shri P. K. Deo]

been if all the hill districts, the Khasi and the Jaintia Hills, the Lushai Hills, the Naga Hills and the Cachar District of Assam could form a separate State with Tripura and Manipur.

I sincerely hope that there would be a return of peace in the Naga area, it won't be a peace of the grave but it will be a peace of the brave, and the qualities of that marshal race would be fully utilised for the defence of the country. The Government of India should extend a hand of co-operation and goodwill, a hand of forgive and forget and there should not be any case for victimisation.

So far as Phizo is concerned, I feel that we should try to win him over and try to utilise his leadership for the betterment of the Nagaland.

If you go through the various demands of the Nagas from time to time you will find that Nagas are in equal number in the bordering areas. There are some Nagas in China and Burma also. Probably they want that all those areas should be brought together so as to form a big Nagaland. If that be so, we should not yield to the demand of the Nagas.

I feel that for the transitional period the interim body should be formed on an elective basis. I could not follow from the statement of the Prime Minister what was meant by saying that representatives from the various Naga tribes should be taken in there. I feel that there should be adult franchise and elected representatives of the area should find a place in the interim body to advise the Governor.

Lastly, from the statement of the Prime Minister I find that even though we claim ourselves to be a secular State the Government is going to safeguard the religious practices of the Nagas. I do not think there is a case to safeguard the religious practices of the Nagas in this context.

Mr. Speaker: Shri Braj Raj Singh. He should take only five minutes. Then I will call upon the hon. Prime Minister.

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी कमियों के बावजूद जो नया राज्य बनने जा रहा है उस का मैं स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आज से सात साल पहले यह घोषणा करके प्रधान मंत्री महोदय बहुत से खूनखराबे को रोक सकते थे लेकिन अफसोस है कि उस समय यह निश्चय नहीं किया गया लेकिन फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद वाली कहावत के मुताबिक जो कुछ निश्चय किया गया है वह स्वागत योग्य है। लेकिन जब ऐसे एक नये राज्य का स्वागत किया जा रहा है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जहां तक उन बातों का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूर्वी सीमा के कुछ हिस्से जिसमें तथाकथित नेफा क्षत्र आता है और दूसरे कुछ क्षेत्र आते हैं वहां पर हम ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे देश के दूसरे हिस्सों से उनका सम्बन्ध कट सा जाता है। मैं मानता हूं कि जहां तक इस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति उनके रहन सहन के ढंग और उनके जीवन के तौर तरीकों का सम्बन्ध है उनकी रक्षा की जानी चाहिए लेकिन रक्षा करने के मानी यह कभी नहीं होने चाहिएं कि उन पर कुछ विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़े और अपने देश के लोगों का उन से सम्पर्क न रहने पाये। मुझे यह कहने में बहुत दुःख है कि जिस क्षेत्र को नेफा कहा जात है उसमें कुछ दिन पहले तक महात्मा गांधी, लक्ष्मी और गौरी की तस्वीरें नहीं रखी जा सकती थीं लेकिन दूसरी कुछ विदेशी तस्वीरें रखने की इजाजत थी। मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब इस क्षेत्र का एक तरह से अपना काम अपने नियमों के मुताबिक चलाने की बात कही जाती है तो उसमें यह भी खयाल रखा जाना चाहिये कि कहीं ऐसी व्यवस्था न हो जाय जिससे उन पर विदेशी प्रभाव बहुत पड़ता रहे। मुझे अफसोस है कि अब तक इस क्षेत्र में विदेशी प्रभाव कुछ इस तरीके का रहा है कि उस की वजह से वहां

के लोग यह चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र देश की तरह रहें। यह आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे एरिया, क्षेत्रफल या इतने छोटे संघ के लोग किस तरह से स्वतंत्र होने की बात सोच सकते थे। अब आज जब यह नागालैंड का नाम उसे दिया जा रहा है तो भले ही उसका नाम कुछ ऐसा हो जो शायद अच्छा न लगे। अब श्री जयपाल सिंह ने सुझाव दिया कि उसका नाम नागालैंड न होकर नागा स्थान हो। लेकिन मैं निवेदन करूं कि जो प्रदेश बनाया जा रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें कोई अलग होने की बात होती है। जब हम दूसरे राज्यों के लिए नहीं कह सकते कि खतरा है तब नागालैंड के नाम से ही किस तरीके का खतरा हो सकता है। भारतीय संविधान के छठवें परिशिष्ट में जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक अभी तक उनका अलग ही प्रबन्ध रहा है और उन से दूसरे राज्यों का सम्बन्ध नहीं रहा है यहां तक कि केन्द्र का उस में भीतर कोई विशेष दखल नहीं रहा है और जिसके कि मुताबिक वहां का दूसरे राज्यों का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में इस तरह की बात करना कि उस प्रदेश के बनने से सेपेरेटिस्ट टेंडेंसीज बढती हैं विघटनकारी प्रवृत्तियां बढती हैं, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हमें देश के हर नागरिक के लिए सोचना चाहिए कि उसकी हिन्दुस्तान के प्रति उतनी ही भक्ति है जितनी कि अन्य किसी और व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए एक व्यक्ति में विश्वास करना और दूसरे के बारे में यह सोचना कि उसमें उतनी भक्ति नहीं है और हम में ज्यादा है यह अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि नागालैंड के निर्माण के सम्बन्ध में कोई इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि कोई स्थायी हल निकाला जाय। मैं समझता हूं कि यह पूर्वी सीमा के और बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिन को कि इकट्ठा कर के एक बड़ा प्रदेश बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मनिपुर में अभी पिछले दिनों बहुत ही शान्तिपूर्ण एक आन्दोलन चला है और उस आन्दोलन के फलस्वरूप सरकार को यह सोचना चाहिए कि उसमें भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें कि नागा लोग रहते हैं और क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि उन नागा लोगों का इस नागा लैंड के साथ एक सम्बन्ध जोड़ा जाय और एक बड़ा प्रदेश कर दिया जाय। नागा लैंड की जो मांग थी वह स्वीकार की गई है। वहां एक प्रदेशीय सरकार बनाने की मांग को लेकर जो वहां एक उस तरह को सरकार बनाने की बात सोची जा रही है मैं चाहता हूं कि सरकार मनिपुर और त्रिपुरा में भी वहां की जनता जो उस तरह की सरकार बनाने की मांग कर रही है, जितनी जल्दी उस मांग को स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा होगा।

मैं इस राज्य के निर्माण का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि नागालैंड के निवासी हिन्दुस्तान को उसी तरीके से अपनी मातृभूमि समझते हैं जैसे कि अन्य देशवासी समझते हैं और इस तरह का कोई मौका नहीं आयेगा जिससे लोगों को यह शक करने की गुंजाइश हो कि वह अधिक देशभक्त हैं और नागालैंड के निवासी कम देशभक्त हैं। मैं चाहता हूं कि हम पुरानी बातों को भुला कर श्री फिजो जो कि भारत से बाहर रह कर अपनी कार्यवाहियों को चला रहे हैं यदि किसी तरीके से उनको अपने देश में ला सकें और उनको फिर हम हिन्दुस्तान का एक सभ्य और अच्छा नागरिक बना सकें तो उस से एक अच्छी भावना पैदा होगी। मैं चाहता हूं कि नागालैंड के निर्माण का सभी लोग स्वागत करें और यह आशा करें कि यह देश का हमेशा के लिए एक अभिन्न अंग होगा जैसा कि रहा है और उन शंकाओं को कोई स्थान नहीं मिलेगा जोकि कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में हैं या कुछ देश के नागरिकों के दिमाग में हो सकती हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अध्यक्ष महोदय,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मुझे खुशी है कि यह प्रश्न यहां लोक सभा में पेश हुआ क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां अभी तक लोगों के दिलों में मालूम होती हैं और शायद मैं इस मौके पर उनको हटा सकूं।

यहां पर इस बात की चर्चा हुई कि एक अलग संविधान बनेगा यह कैसी बात है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि एक अलग संविधान का प्रश्न इसमें कहां उठता है और कहां वह बनने वाला है। अब अलग से तो कोई संविधान बनने का इस में कोई सवाल ही नहीं है जड़ से नहीं है। आधे या चौथाई का सवाल भी नहीं है। अब जो लोगों को एक धोखा हो गया है वह शायद इसलिए हो गया है कि जो एक मजमून नागा डेलीगेशन ने तैयार किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि जब हम से यह फैसला हो जाय जिसको कि वह पोलिटिकल फैसला कहते थे तो उन्होंने कहा था कि उस फैसले के हो जाने के बाद वे अपना कांस्टीट्यूशन बनायेंगे। इससे शायद लोगों को धोखा हो गया लेकिन हम ने उन से कहा कि यह बात तो हो नहीं सकती। कांस्टीट्यूशन बनता है लोक सभा में और कहीं पर वह नहीं बनता है। लेकिन एक चीज वह बना सकते हैं जो कि कांस्टीट्यूशन नहीं है लेकिन जिसको कि आप बाईलाज कह सकते हैं जैसे बाईलाज कि म्युनिसपैल्टीज बनाती हैं या उसी तरह की कोई और बौडी बनाये। इसलिए यह बात साफ हो जाती है कि कांस्टीट्यूशन बनाने की बात तो है ही नहीं।

दूसरी चीज यहां पर यह कही गई कि एक बात इस में पूरी तौर से साफ नहीं है। इंटैरिम पीरियड, ट्रैंजीशनल पीरियड और कई ऐसी बातें कही जाती हैं। अब पहली बात तो यह है कि हम ने उनको स्वीकार किया यकीनन् एक स्टेट की हैसियत से लेकिन उसमें बिलफेल एक अटकाव है, लिमिटेशंस हैं। एक तो यह कि कई दर्जे हैं। कुछ थोड़ा सा समय लगता है कानून बनाने में और उसके करने में चन्द महीने लगते हैं। दूसरे यह कि उसके बनने के बाद भी जब तक कि वहां कोई झगड़ा फिसाद हो तो ला एंड आर्डर और किसी कदर फाइनेंस भी गवर्नर की निगरानी में रहेंगे। तीसरी बात यह कि त्वेनसांग ऐरिया के सिलसिले में यह उनकी खुद मांग थी कि वहां पर दस वर्ष तक कोई कांस्टीट्यूशन हो ही नहीं और वह गवर्नर के नीचे रहे। उनकी खुद मांग थी। हमने हूबहू जो उन्होंने त्वेनसांग के लिए मांगा था अगर आप उसको पढ़ें तो पायेंगे कि हमने उसको उसी तरह कबूल किया क्योंकि त्वेनसांग वाले जो यहां आये थे वे भी मौजूद थे और उनकी खुद यह मांग थी। यह तो ठीक है कि हम उनको सबको नागाज कहते हैं लेकिन उनमें भी बहुत कुछ दर्जे हैं और अलग अलग ट्राइब्स हैं और अलग अलग खिंचातानी है। तो उन्होंने खुद कहा है कि दस बरस तक ऐसे ही रहें। उन के कुछ नुमायंदे आयेंगे—उन की जो कुछ असेम्बली बनेगी, लेकिन उस के लिए असेम्बली कुछ कायदे-कानून नहीं बना सकती। वह एक रिजर्व्ड सबजेक्ट रहेगा। यह उन की मांग थी। दस बरस के बाद क्या हो, यह उस वक्त विचार हो। लेकिन मोटी तौर से यह कहा जाये कि हम ने स्टेट मन्जूर किया। हम ने तो पूरी तौर से किया, लेकिन जब तक वहां दंगा-फ़साद पूरी तौर से खत्म न हो जाये, उस वक्त तक ला एंड आर्डर एक महफूज मजमून है, हालांकि यह उन की सलाह से होगा। हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी ला एंड आर्डर का प्रश्न तय हो जायगा।

श्री त्यागी : ला एंड आर्डर रिजर्व्ड सबजेक्ट रहेगा गवर्नर के साथ ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी हां, उस वक्त तक, जिस वक्त तक कि झगड़ा-फ़साद है।

यह सही है कि उस मौके पर भी गवर्नर का फ़र्ज होगा कि अपने सलाहकारों से सलाह

कर के काम करे, यानी जो उन के नागा एडवाइज़र होंगे, उन से । यह और बात है ।

अब विलफ़ेज़ जो बिल्कुल ही एक ट्रांज़ीशनल पीरियड है—मालूम नहीं वह कितने दिन चले, साल भर चले, डेढ़ बरस चले, जो कुछ चले—उस में वह अपने कुछ एडवाइज़र चुनेंगे । अभी तक वह मामला ठीक नहीं है कि वह कैसे होगा, यानी वह अपनी कौंसिल चुनें, या कुछ थोडे से एडवाज़र चुनें, जिन की सलाह से गवर्नर काम करेगा, लेकिन उस से गवर्नर का अधिकार कोई कम नहीं होगा, वे एडवाइज़र उन का कहना मानें या न मानें । यह हमारा कांस्टीच्यूशन बदलने की बात नहीं है । यह हम एक रेगुलेशन से भी वहां ला सकते हैं । इस समय भी रेगुलेशन से—कांस्टीच्यूशन में उस का इन्तज़ाम है, मुझे आर्टिकल याद नहीं है,—उस को और सिक्स्थ शिड्यूल दोनों को मिला कर जब चाहे हम ला सकते हैं कि वह एडवाइज़री कौंसिल वहां बना दें और उस में से दो तीन आदमी विशेष कर एडवाइज़र हों गवर्नर के । इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : लेकिन आप ने यह ज़िक्र किया था कि एक ट्राइब्ज के नुमायंदे को ले कर एक कौंसिल बनेगी, जो एडवाइज करेगी गवर्नर को **इन डिसचार्ज आफ़ हिज फक्शन्ज** ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यही तो मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी एडवाइज़री कौंसिल हो ट्राइब्ज की और दो तीन विशेष एडवाइज़र हों, जिन से उन का सम्बन्ध ज्यादा हो । हम यह करने में इन्तज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस मामले में, और हर मामले में, हम उन की सलाह से चलना चाहते हैं । कोई मजबूरी नहीं है । मेरा विचार है कि शायद कल या परसों, इन दो तीन दिनों के अन्दर, उन की फिर एक बैठक हो रही है इन बातों पर विचार करने के लिए । तो जो वे सलाह देंगे, उस पर विचार कर के हम थोड़े दिन में रेगुलेशन निकाल कर उस को कर देंगे । हम जानते नहीं हैं । मैं इस समय नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ी कौंसिल हो, जिस में ट्राइब्ज के नुमायंदे हों । वहां बहुत सारे ट्राइब्ज हैं । मालूम नहीं १६, १७ हैं, कितने हैं ।

एक माननीय सदस्य : सिक्स्टीन ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, सोलह हैं । ऐसे मौके पर गिनती से काम नहीं होता है । सब ट्राइब्ज को वहां होना है । आप कहें कि बड़ा ट्राइब है या छोटा ट्राइब है, इस से काम नहीं चलता है। तो जैसे वे कहेंगे, जैसे वे बनायेंगे उस को हम स्वीकार कर लेंगे और फिर शायद वही कौंसिल अपने में से दो तीन चुने, जो कि विशेषकर सलाहकार हों गवर्नर के । यह तो हो सकता है रेगुलेशन से ।

फिर दूसरा कदम उठेगा, जब कि यह लोक सभा, यह पार्लियमेंट, कांस्टीच्यूशन में जो कुछ थोड़ा सा बदलना है, उस को बदल दे । तब और होगा । तब और होने पर भी, जैसे मैं ने आप से कहा, गवर्नर का अधिकार ला एंड आर्डर के ऊपर कुछ रहेगा और ट्यूनसांग अभी अलग ही रहेगा उन्हीं की दरख्वास्त से । मैं आप को बताऊं ट्यूनसांग की निस्बत, जो कुछ उन्होंने हम से कहा था :—

> "The Governor shall carry on the administration of the Tuensang District for a period of 10 years or till such time as the tribes in the Tuensang District are capable of shouldering more responsibilities of the advanced system of administration. The commencement of the ten-year period of the administration will start simultaneously with the enforcement of the detailed working of the Constitution in other parts of the Nagaland".

फिर उस में और तफ़सील है लम्बी सी कि कैसे चले । लेकिन बुनियादी बात यह है कि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन्होंने खुद उस से दरख्वास्त की—ट्यूनसांग वालों ने दरख्वास्त की कि दस बरस तक आप इन्तजार कीजिये। हम ने उस को मन्जूर किया।

"At the end of the ten year period the situation will be reviewed and if the people so desire the period would be further extended".

यह तो उन की मांग है।

मैं आप को बताऊं कि कोई बारह बरस हुए, जब से ये सवाल मेरे सामने आये। मैं तो उस समय बहुत ज्यादा जानता नहीं था भारत के इस हिस्से को। लेकिन जहां वे आये, मुझे दिलचस्पी हुई। मैं गया भी। वहां मिला भी लोगों से और यों भी आम तौर से मुझे पहाड़ी लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन नागा लोगों से मुझे खास कुछ मुहब्बत सी होने लगी थी, उन के जिस्म से, उन के रंग-ढंग से, उन के सीधे खड़े रहने से, सीधे देखने से, सिर नहीं झुकाने से। एक माकूल लोग थे। मैं ने कहा, यह तो एक दौलत है किसी मुल्क के लिए। हमारे लिए ऐसे लोगों को अपनाना तो हिन्दुस्तान की एक ताकत होगी। उस वक्त से यह बात है। यह मैं नहीं कहता कि हम से या आसाम गवर्नमेंट से गलतियां नहीं हुईं। वह दूसरी बात है। होती हैं, क्योंकि वह जमाना अजीबो-गरीब था। हम फंसे थे अपनी बातों में, पार्टीशन के बाद यहां झगड़े-फ़साद थे, और बातें थीं। हुई गलतियां। कोई कश नहीं है। लेकिन बहरसूरत मेरे सामने यह बात थी कि उन को कैसे अपनायें, क्योंकि मैं उन की कद्र करता था। यों भी चाहता मैं, लेकिन उस से ज्यादा मैं उन की कद्र करता था कि वे आयें। शुरू से, जब से फ़िजो साहब मुझ से मिलने आये—दो दफ़ा मिले, एक दफ़ा यहां दिल्ली में, जैसा कि उन्होंने कहा है, जयप्रकाश सिंह जी की कुछ मदद से आये थे और दूसरी दफ़ा मैं मैं आसाम में उन से मिला था—मैं ने उन से और उन के जो साथी आये थे, उन से कहा कि हम पूरी तौर से आज़ादी—आटानोमी देना चाहते हैं आप को, हर एक को। अव्वल तो मैं ने कहा कि "आप इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इंडिपेंडेंट आप हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, आप इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंस मैं कहां से ला कर दूं। आप का मुल्क है। आप उतने ही इंडिपेंडेंट हैं, जितना मैं हूं।" लेकिन मैं ने कहा कि "अगर आप भारत से अलग होना चाहें, यह बात मैं आप से नहीं करूंगा। सीधी बात है।" मैं ने कहा, "यह फिजूल बहस है। मैं उस की बहुत सारी वजूहात पेश कर सकता हूं। फिजूल वक्त जाया करना है और उस को छोड़ कर पूरी आटानोमी आप को होनी चाहिए। यह मेरी राय है, आप के दबाव की बात नहीं है।" शुरू से मेरी यह राय थी और शुरू से उन से कहा गया था। कोई नई बात उन को नहीं दी गई।

वहां फिर फ़िजो ने झगड़ा-फ़साद शुरू किया। पहले तो कुछ पर्दे के पीछे—पर्दे के पीछे से मतलब, ऊपर से हम से बातें होती थीं और पर्दे के पीछे जाकर उन्होंने इसका इन्तजाम किया और पहले ट्यूनसांग में किया, नागा हिल्ज में नहीं किया। पहले ट्यूनसांग में उन्होंने झगड़ा-फ़साद शुरू किया फिर आगे। खैर वह बढ़ता गया। उस बढ़ने की वजह से जो कार्रवाई हम करना चाहते थे वहां, वह हम नहीं कर सके, क्योंकि जब झगड़ा-फ़साद है, बलवा है, तो कैसे हम यहां ये बातें, यह अमेंडमेंट करें।

हां, एक बात थी। मैंने उस वक्त यह नहीं सोचा था कि एक सोलहवां राज्य इस को बनायें। यह ख्याल उस वक्त दिमाग में नहीं आया था क्योंकि हमारे दिमाग चलते थे बड़े बड़े राज्यों में, छोटे नहीं। लेकिन यह मेरा जरूर ख्याल था कि वहां, और और जगह, पूरी आजादी दी जाये। जिस ढंग से हम अपने कांस्टीच्यूशन में दे सकें, दें।

तो जब फिर तीन बरस हुए, सन् १९५७ में, वहां हालत कुछ अच्छी हुई और वे लोग मिले, अपना कनवेन्शन किया, तो हमनें उसका स्वागत किया और कन्वेन्शन के बाद उन्होंने चन्द बातें पेश कीं । पहली बात यही थी कि ट्यूनसांग और नागा हिल्ज एरिया को मिला दिया जाये और ये दोनों एक्सटर्नल एफ़ेयर्ज़ मिनिस्ट्री के नीचे रखे जायें । अब इसमें लोग शिकायत करते हैं और समझते हैं कि इसमें कोई चालबाजी है लेकिन उस समय की हालत को देखते हुए यह एक बिल्कुल मामूली बात थी, क्योंकि नागा हिल्ज का उस वक्त तक सम्बन्ध आसाम से था, ट्यूनसांग का था नेफा से और नेफ़ा का था एक्सटर्नल एफ़ेयर्ज मिनिस्ट्री से । वे कुछ नाखुश हो गये थे अपने आसाम के सम्बन्ध से । क्यों, वाजिब था या नहीं, यह दूसरी बात है । असल में वे उससे अलग होना चाहते थे, ज़ाब्ते से और नेफ़ा के ज़रिये वे एक्सटर्नल एफ़ेयर्ज मिनिस्ट्री को जानते थे । वे चाहते थे कि हमारा साथ हो उससे । तो यह सवाल होम मिनिस्टरी या एक्टर्नल एफेयर्स मिनिस्टरी का कभी उठा नहीं । असल में देखा जाए तो यह एक अन्दरूनी मामला है कि कौन मिनिस्टरी किस काम को करे । इस तरह की चीज़ को कांस्टीट्यूशन में कोई नहीं लिखता और न कोई लिखेगा । यह अन्दरूनी मामला है । तो ये जो हिस्से हैं जिनको कहा जाए कि सैटल्ड हिस्से नहीं हैं, जहां पर कि मामूली कांस्टीट्यशन नहीं चलता वे एक्सटर्नल सफेयर्स मिनिस्टरी के पास रखे गये थे, बोर्डर एरियाज़ वगैरह, जैसे नेफा एरिया है । इसलिये कि जब वे सैटल हो जायें तो होम मिनिस्टरी के सुपुर्द हो जायेंगे । तो जब वक्त आएगा देख लेंगे । वहां खास सवाल उठते थे, पेचीदा सवाल उठते थे, बोर्डर के, इसके, उसके, फौज के, असम राइफल के और असम राइफल एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टरी के नीचे है । तो यह जो तसवीर है, यह उनके सामने थी । इसलिये उन्होंने तीन साल हुए कहा कि आप इसको एक माने में जोड़ दें तुएनसांग में जो कि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री में है । हमने इसको मंजूर किया और और पार्लियामेंट में बात रखी गई और पार्लिमेंट ने इसको स्वीकार किया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि तीन बरस से मामला अटका हुआ है, इसको पहले तय क्यों नहीं किया गया । औरों ने भी इस बारे में कहा है । जब से यह बात उठी है, तीन बरस हुए, हम इन्तिज़ार कर रहे हैं उनके फैसले का । उस वक्त उनकी जो कनवैंशन हुई उसका पहला फैसला जो हुआ वह मैंने आपको बता दिया है । उसको हमने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हम और सोचेंगे । उन्होंने फिर अपनी छोटी छोटी कमेटियां बनाई और उन कमेटियों ने साल साल डेढ़ डेढ़ साल इस पर सोच विचार करने में लगा दिया । फिर उनकी दो तीन कनवैंशनें हुई और यह तीसरी कनवैंशन थी । तो हमारी तरफ से इसमें कोई ढील या डिले नहीं हुई सिवाय इसके कि आप कहें कि उनका आखिरी फैसला पिछले अक्तूबर में हुआ था और अब अगस्त है । यह बात आप कह सकते हैं । लेकिन उनका फैसला जहां तक मेरा ख्याल है जो हुआ था उसकी झलक गवर्नर के पास दिसम्बर में आई थी । मेरे पास नहीं आई । उन्होंने इसको पेश किया और कुछ इनफार्मली मिले, बेज़ाब्ता मिले । मुझे उन्होंने अप्रैल में लिखा और उसके दो या तीन हफ्ते बाद मैं यूरोप जा रहा था । मैंने उनसे कहा कि कि मैं इस वक्त आप से मिल नहीं सकता हूं, वापिस आकर मिलूंगा तो हमारी तरफ से कोई खास देर नहीं हुई । मुमकिन है महीना भर आगे हो जाता या पीछे हो जाता । तो हम मिले । तीन बरस गुज़रे नहीं हैं । तीन बरस उनके सोचने में, आपस में बहस करने में लगे हैं । बीच में उन्होंने यह भी कोशिश की थी कि जाकर जो लोग होस्टाइल्ज हैं, जो अण्डर-ग्राउण्ड कहलाते हैं, उनसे भी मिला जाए और उनको भी अपनी तरफ खींचा जाए । उनमें से कुछ लोग खिंचे भी ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ । तो जो वक्त सर्फ हुआ वह उनकी तरफ से हुआ । आखिर में वे हमारे पास आए और कहने लगे कि बहुत से लोग हमारे साथ हैं और वे लोग मानते नहीं हैं, और हम यह चाहते हैं । हमारे सामने सवाल हुआ अव्वल तो यह कि ये लोग पूरे तौर पर से जिम्मा नहीं ले सकते हैं कि शान्ति हो जाएगी और साफ कहते हैं कि हां हम पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हो जाएगी हल्के हल्के लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि एक दम से वे लोग हथियार डाल देंगे । दूसरा सवाल हमारे सामने यह पैदा हुआ कि जो चीज वे मां ते हैं वह मुनासिब है वाजिब है या नहीं है ।

तो जो चीज व मांगते थे, उसमें मुझे कोई खास एतराज नहीं था । जरा मेरा दिमाग अटकता था दो तीन बातों पर । एक तो यह थी कि इतनी छोटी सी स्टेट हम बनायें क्या यह ठीक है । स्टेट देने में मुझे कोई एतराज नहीं था । लेकिन छोटी सी स्टेट और स्टेट को चलाने का जो बोझा होता है वह उन पर पड़े, एक सुपरस्ट्रक्चर का, एक गवर्नर और यह और वह, काफी खर्चा होता है, मिनिस्ट्रीज सब होती हैं, यह मैं सोचता था । पैसे की तरफ मेरा ख्याल था । मेरा ख्याल ज्यादा इस तरफ था कि ज्यादा खर्चा न हो और टीमटाम न हो ।

दूसरा मेरा दिमाग जो अटका वह इस लिए अटका कि एक नया नागालैण्ड हो । नागालैण्ड नाम मुझे बुरा नहीं लगता है । लेकिन बहरसूरत एक नई तरफ जाना था । अब तक जो नाम हैं हमारे प्रदेशों के, राज्यों के वे दूसरी ही तरह के हैं । लेकिन फिर भी ये दोनों बातें ऐसी नही थीं, मेरी राय में और उसूल की वजह से, कि मैं उन से झगड़ा करता । मैंने उनसे कहा कि मुनासिब हो कि आप नागालैण्ड के बजाय कोई दूसरा नाम रख दें, ट्राइबल नाम कुछ भी हो, रख दें ताकि वह नाम हम को भी पसन्द हो । उन्होंने कहा कि नहीं हम यही रखेंगे । मैंने कहा कि अगर आप इसरार करते हैं तो मुझे स्वीकार है मैं बहस नहीं करूंगा । और भी एक बात है और उनका दूसरा करना बेमानी नहीं है । पिछले दस बरसों से उनकी सारी तहरीक इससे बंध गई थी, इस शब्द से बंध गई थी, इस नाम से बंध गई थी और अगर इसको न किया जाता तो जो दुश्मन हैं वहां, वे उससे फायदा उठाते । तो नागालैण्ड कहें या कुछ और, हमने मंजूर कर लिया । जहां तक नाम का सम्बन्ध है, वह बुरा नाम नहीं है ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वाका तो यह है और आप इसको याद रखें कि वह एक अलग स्टेट तो नहीं है लेकिन एक अलग हिस्सा हिन्दुस्तान का कई बरस से है । यानी हम कोई रिआर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हैं । हम नए एरिया की कोई नई स्टेट नहीं बना रहे हैं । हम इसको किसी से अलग नहीं कर रहे हैं । असल में अलग तो वह जमाने से था । अगर जाब्ते से पूछिये तो वह अलग था और अब तीन बरस हो गए हैं उसको अलग हुए । अलग उनका एडमिनिस्ट्रेशन है । यह कोई रिआर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी और स्टेट के हम दो टुकड़े नहीं कर रहे हैं । खाली हमारे सामने सवाल था कि एक जो चीज अलग है उसको अधिकार हम कितने दें । इतना ही सवाल था कि स्टेटस क्या दें, अधिकार क्या दें । अधिकार देने को हम हमेशा राजी थे, शुरू से राजी थे । खाली जो हम अटके तो इसी बात को लेकर कि स्टेट उसको कहे तो स्टेट के साथ धूमधाम होती है और क्यों बांधें इसके साथ खर्च को । सिर्फ इतना ही सवाल था । दूसरा कोई सवाल नहीं था। जो खर्चा नई स्टेट में होगा वह आखिर उससे कम ही होगा जो हम कर रहे हैं, बाद में ज्यादा नहीं होगा, चाहे इधर हो या उधर हो । तो जब वे मुझ से मिले तो मैंने उनसे कहा कि आप स्टेट कहते हैं, स्टेट आपको मुबारिक हो, मुझे कोई एत-

राज नहीं है लेकिन अगर आप समझते है कि और स्टेट्स में हमारे यहां टीमटाम है वह सब आपके यहां भी हो तो मुझे उसमें ऐतराज है, स्टेट्स के लिये नहीं है । किसी कद्र मेरा यह ख्याल है कि गलती से हम फंस गए हैं इस सब टीमटाम में मेरा मतलब गवर्नर वगैरह से है । सारा खर्च हमारे ऊपर है । फंस गए तो फंस गए, निकलना मुश्किल है ।

श्री बजराज सिंह : कोशिश तो कीजिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरु : तो यह सब कुछ नागालैण्ड में हो, यह तो बर्दाश्त की बात नहीं है । मैंने कहा कि जो मुनासिब खर्चे हैं और जगह बड़ी बड़ी स्टेट्स में, मिनिस्टरीज हैं और यह है और वह है, यह सब चीज आपके यहां मौजूद नही होगी । इस किस्म के खर्चे जरा सी जगह के लिये, जो कि दिल्ली के मुहल्ले के बराबर है, मुनासिब नहीं मालूम देते हैं । उन्होंने कहा कि हां हम मंजूर करते हैं कि इस किस्म के खर्चे न हों और हमारे यहां खर्चे का जो हिसाब लगाया जाए वह दूसरे ढंग से हो और नक्ल न की जाए और स्टेट्स की । जो मिनिस्टर्स हों या कुछ और हों, वे हमारे ढंग से हों । फिर आप जानते हैं कि यह मंजूर हुआ कि गवर्नर वहां कोई अलग न हो और हाईकोर्ट भी इसी तरह है । तो आप गौर करें और देखें कि सिर्फ एक ही बात हुई है और वह बात अहमियत रखती है, यह मैं मानता हूं । एक जो अलग एंटिटी थी, एक माने में एक अलग स्टेट थी जिसका स्टेट्स कम था, जिसकी पावर्स नहीं थी, उसको पावर्स हमने दी हैं और स्टेट्स दिया है । एंटिटी वही रही, कहीं से काटा नहीं, कहीं से लिया नहीं और न किसी को दिया और जो बात हम चाहते थे खास तौर से, यनी उन लोगों को अपनाना उसकी कोशिश की गई है । असल चीज यह है कि दस बरस से कोशिश हमारी यह रही है चाहे वहां फौज जाए या कोई जाए, कि उन लोगों को अपनाया जाए उन्हें अपनी तरफ लाया जाए और वह हिस्सा भी हिन्दुस्तान का एक मजबूत हिस्सा हो जाए, अंग हो जाए, उस कोशिश को कामयाब बनाने के लिये मैं समझता हूं कि हमने अच्छा कदम उठाया है ।

17 hrs.

अब मैं कैसे पक्के तौर से कहूं कि कितने दिन में वे झगड़ा फिसाद खत्म कर देंगे या और क्या क्या कदम उठेंगे । लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे झगड़ा फिसाद ज्यादा दिन तक, बहुत दिन तक नहीं चलेगा । थोड़ा बहुत चलेगा, वह और बात है ।

बहरसूरत जो भी कुछ हुआ वह मैंने आपके सामने रख दिया है और मैंने राय दी इस कदम को उठाने की और इस चीज को आपके सामने पेश कर दिया । अक्सर होता है कि वाकयात के दबाव, से, कम्पलशन आफ इवेंट्स से कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और बहुत दफा पीने पड़ते हैं । लेकिन इस मामले में कड़वा घूंट यह मेरे लिए नहीं था । यह मैंने खुशी से मंजूर किया है, सही समझ कर मंजूर किया है और सही समझ कर आपके सामने पेश किया है । मैं आप से साफ साफ कह दूं कि एक बात का और ख्याल था हालांकि उससे इसका कोई सीधा ताल्लुक नहीं है । जो विचार था वह यह कि इसका असर भारत के और हिस्सों पर भी पड़ेगा जैसे कि किसी भाई ने कहा कि साहब इसका असर अकाली आन्दोलन पर पड़ेगा । तो यह ख्याल था हालांकि इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह एक अलग चीज है । अलग स्टेट है । होमोजीनियस स्टेट है । पूरी तरह से अलग है और उनको कुछ अधिकार देना था । किसी से अलग नहीं करना था । लेकिन सम्बन्ध हो या न हो, लोग उससे फायदा उठा सकते हैं । अब सिवा इसके और क्या किया जा सकता है कि उनके दिमाग से इस गलत फहमी को दूर किया जाए । लेकिन इसकी वजह से हम दूसरी जगह नाइन्साफी करें यह तो मुनासिब नहीं मालूम देता ।

जैसा मैंने कहा कि यह तो एक्सटरनल एफेअर्स मिनिस्ट्री का सवाल है, तो इसका

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जिक्र कांस्टीट्यूशन में नहीं होगा, वह तो एक अन्दरूनी इन्तिजाम की बत है, और यकीनन मौका आएगा–मेरी तो जाती राय है–कि होम मिनिस्ट्री इसको ले ले। लेकिन वह लोग तो हमारे सारे कांस्टीट्यूशन को समझते नहीं थे। एक चीज को जानते थे पहचानते थे और उन्होंने कहा कि दूसरी चीज शायद ठीक न हो। इसलिए उनसे बहस करके उनके दिल में शक पैदा करना मुनासिब नहीं समझा और हमने मंजूर कर लिया। और इतनी मंजूर करने की बात भी नहीं थी। इस वक्त यही हो सकता है। अगर हम ऐसा न करते तो हमको सारा सिलसिला नेफा का बदलना होता और उसको होम मिनस्ट्री में लाना होता जो कि बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जो हमने सरविस बनायी है नेफा वगैरह के लिए वही वहां चल सकती है। वहां खास किस्म के आदमी ही जा सकते हैं। आपका मामूली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सरविस का आदमी वहां नहीं जा सकता। नहीं जा सकता इसलिए कि कई बातें हैं। एक तो इसलिए कि जो लोग वहां जाएं उनके शरीर बड़े तगड़े होने चाहिए। जो जरा भी ढ़ीला हो वह वहां नहीं जा सकता, उसको फिजीकली फिट होना चाहिए, फिजीकली स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरे जो लोग वहां जाते हैं उनकी सारी दुनिया से अलग रहना होता है, वहां दुनिया के कम्फर्ट, सिनेमा वगैरह नहीं हैं। वहां कोई तमाशा नहीं है। वहां जंगलों में रहना होता है, हिम्मत से रहना होता है, तमाशों से दूर रहना होता है, अक्सर अपने परिवारों से अलग रहना होता है। इसलिए लोग वहां जाने के लिए आसानी से राजी नहीं होते। इसलिए हमने वहां के लिए एक खास पोलीटिकल सरविस बनायी और उसके लिए कुछ आदमी फौज से चुने गए और कुछ दूसरी सरविसेज से लिए गए। उनको ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो उनको अगर हम एक दम से मिला देते तो दिक्कत पेश आती क्योंकि दूसरे लोग वहां जाने से इन्कार करते।

डा० मा० वी० अणे (नागपुर): आप के हिसाब से आपने इसको एक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री में रखना ठीक समझा?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जैसा मैं ने कहा इस वक्त यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। चाहे वह मानते या न मानते, इस वक्त यही हो सकता है। लेकिन जब गाड़ी चलने लगे तो अच्छी बात हो कि वह और स्टेट्स की तरह होम मिनिस्ट्री में चला जाए।

मुझे कोई शक नहीं और जो खबर हमारे पास आयी है उससे भी यही पता चलता है कि जो हमने यह आरजी फैसला किया है उसका नागा लैंड में अच्छा असर हुआ है। आप याद रखें कि यह असर किन पर पैदा करना है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि साहब जो फिजो के साथी हैं उन पर क्या असर हुआ होगा। मैं नहीं जवाब दे सकता इसका, गालिबन कोई असर न हुआ हो या बुरा असर हुआ हो। मैं नहीं जानता कि फिजो के साथी कितने हैं। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि वह १० फीसदी हों या १५ या २० फीसदी हों। फर्ज कर लीजिए कि यह जो लोग हमारे पास आए थे ये २० या २५ फीसदी हैं। लेकिन बीच में ६० या ७० फीसदी ऐसे लोग हैं जो कि न किसी सूरत में फिजो के साथी हैं और जो न गिरे पड़ते हैं हमसे गले मिलने को। वह बेचारे अपनी जिन्दगी बसर करना चाहते हैं शान्ति से और किसी कदर आराम से और आजादी से। तो हमारे सामने सवाल यह है कि इन ६०–७० फीसदी को कैसे खींचें अपनी तरफ। जो दुश्मन के तौर पर अलग खड़े हुए हैं उन को हिलाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन ६०–७० फीसदी को अपनी तरफ खींच सकें तो ८० फीसदी आबादी को हम अपनी तरफ कर लेंगे। तो देखना यह है कि इन लोगों पर क्या असर होत है जोकि बीच के लोग हैं। जो लोग बीच के होते हैं वह ज्यादातर पोलीटिकली माइडेड नहीं होते। वह अपने घर में इज्जत से रहना चाहते हैं उन को हमें अपनाना

हैं । मेरा खयाल है कि जो कनवेंशन के लोग यहां आये थे वह किसी कदर उन की नुमायदगी करते हैं और उन के ऊपर अच्छा असर हुआ ।

किसी साहब ने कहा कि वह ईसाई है, लेकिन पूरे तौर से यह बात सही नहीं है । आबादी के लिहाज से बहुत कम ईसाई हैं । ज्यादातर को मैं नहीं जानता कि क्या कहूं । उन को हिन्दू कहना सही नहीं होगा । जो उन को हिन्दू समझते हैं वह गलत समझते हैं । बहर-सूरत, वह न ईसाई हैं और न हिन्दू हैं बल्कि एनिमिस्ट हैं । लेकिन यह बात सही है कि जो वहां ईसाई नागा हैं लीडरशिप उन की ही है । इस की वजह यह है कि वही पढ़े लिखे हैं । उन को उनकी भाषा रोमन लिपि में पढ़ाई गई है । उन को मिशनरीज ने ही रोमन लिपि में पढ़ाया है । पढ़े लिखे होने से अधिकतर वही लीडर हैं हालांकि गिनती में वह कम है ।

यह कहा गया कि वहां जाने से लोगों को रोका जाता है, लशायद ब्रजराज सिंह जी ने यह कहा था । अंग्रेजों के जमाने में भी लोगों को वहां जाने से रोका जाता था लेकिन उस की कुछ और वजुहात थीं ।

हम ने भी इस पर गौर किया और हम ने देखा कि जो लोग वहां भारत के और हिस्सों से जाते हैं वह बहुत गड़बड़ी पैदा करते हैं । कौन लोग यहां भारत के और हिस्सों से आते थे ? आम तौर से व्यापारी आते थे । और व्यापारी आ कर उन्हें बुरी तरह से एक्सप्लाइट करते थे । वह निहायत सीधे सादे आदमी हैं, उन को मारकेट इकानमी वगैरह से क्या मतलब । लोग यहां से जा कर उन को धोखा देते थे और एक्सप्लाइट करते थे और उन के टेस्ट को भी खराब करते थे । यहां से सस्ते फैबरिक्स ले जा कर उन की सुन्दर चीजों को मारकेट से निकाल देते थे । हम यह पसन्द नहीं करते, इसलिये हम ने उन को रोका । हम ने उन की काटेज इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया और यहां की चीजों के लिये भी कोआपरेटिव्स खुलवाईं ताकि वह चीजें उन को उन के मारफत मिलें और उन का एक्स्प्लायटेशन न हो ।

दूसरे बाहर के लोग वहां जा कर जमीन खरीदते हैं, यह झगड़े की बात है । वहां जमीन की ज्यादा कद्र है जैसी कि और जगह भी है । अगर कोई बाहर का आदमी वहां जा कर किसी को दस पैसे का लालच दे कर जमीन खरीदे तो झगड़े पैदा होते हैं । तो हमने उन की जमीन को प्रोटेक्ट किया । याद रखिये कि हमारे कांस्टीट्यूशन के छठे शिड्यूल में एक खास क्लाज है जिस में हिली एरियाज में जमीन को बचाने का प्रावीजन है ।

एक और भी दिक्कत होती थी । हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां गये और पोलीटिकल आफिसर गये, उन के नौकर चाकर भी गये और कंट्रैक्टर भी गये । उन से भी परेशानी पैदा हुई—एडमिनिस्ट्रेटर्स से नहीं क्योंकि उन को तो हम समझा देते थे, लेकिन जो उन के हाली मवाली उन के साथ जाते थे, वह नहीं समझते थे कि वह कैसा मुल्क है । तो झगड़े होने लगे, कभी औरतों के सिलसिले में कभी किसी और वजह से । वहां ट्राइबल बलवे हो जाते थे अगर हमारे किसी नौकर चाकर से किसी औरत का ताल्लुक हो गया । तो हम झगड़ों में फंसे । इसलिये हम ने इस को रोका ।

और एक चीज है जो हर आदमी को जो वहां जाय समझनी चाहिये । यह लोग—मैं इस वक्त नागाओं के बारे में नहीं कहता—आप इन को किसी कदर वहशी कह लीजिये—हालांकि यह पूरे तौर से ऐसे नहीं हैं, बाज बातों में हैं बाज में नहीं हैं—तगड़े लोग हैं, बेइज्जती को बरदाश्त नहीं कर सकते । जैसे यहां गालीगलौज को लोग बरदाश्त कर लेते हैं, वहां नहीं करते ।

श्री त्यागी : (देहरादून) : अच्छा है ।

श्री जवाहरलाल नेहरु : अगर त्यागी जी वहां जायें तो इन को बहुत फूंक फूंक कर कर कदम बढ़ाना होगा ।

वहां एक बहुत बड़ा इंसीडेंट हुआ जोकि आज तक याद किया जाता है । कोई चालीस पचास बरस हुए कि एक अंग्रेज वहां एक काफिला और कुछ फौज ले कर गया । वह उन की किसी चीज पर, उन के किसी कस्टम पर हंस दिया, उस ने उन के कस्टम का मजाक उड़ाया । उसी रोज रात को वह सारा काफिला और वह अफसर कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन लोगों ने समझा कि इस तरह हंस कर उस ने उन की बेइज्जती की थी । तो आप देखें, यह तो वहां का टैम्पर है । ऐसे तो वहां लोग हैं, सिम्पल लोग जोकि जरा भी नाराज हो जायें तो बदला लें । इसलिये वहां पर आम तौर से भेज देना बड़ा खतरनाक है और झगड़ा बढ़ सकता है : मैं ने कोशिश की कि न वहां पर ठेकेदार जायें और न ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग जायें । कुछ जाना ही पड़ता है । इस तरह से रोकथाम हो । अब हमारे सामने एक नया सवाल पेश हुआ है, कुछ और वजूहात से, वहां के लोगों से नहीं, कुछ हमारी फौजें वहां सरहद के पास हैं । इसलिये मैं ने लम्बे लम्बे सरकुलर्स भेजे हैं फौज को समझाने के लिये कि कैसा उन के साथ बर्ताव किया जाय । अब उनके साथ फौजी धमकियां नहीं चलती हैं बल्कि जरूरत है उन को अपनाने की । उन को अपनाओ, उन से दोस्ती करो और न तो उन की औरतों में और न किसी और चीज में कोई दखल दो । इसलिये आप समझें कि यह आसान बातें नहीं थीं । ऐसा नहीं था कि हम दरवाजा खोल दें और हर एक यहां से उधर चला जाय और जिस से कि हमारे लिये वहां पर नई नई प्राब्लम्स उठ खड़ी हों । इसलिये आप इन सब मसलों पर गौर करें ।

आप देखेंगे कि हालांकि जो बात हम करते हैं वह एक मानी में एक नया कदम है क्योंकि हम एक छोटी सी जगह को लेकर एक नया राज्य बनाया चाहते हैं लेकिन वह कोई रिकौंस्टीट्यूशन नहीं है और वह कोई रिआर्गेनाइजेशन आफ स्टेट्स नहीं है बल्कि वह तो एक छोटे से इलाके को स्टेटस देना है और अधिकार देना है । वह बिलकुल एक होमोजैनस शकल की चीज है । अब वाकया तो यह है कि उसकी सारी बैकग्राउन्ड आपकी और हिन्दुस्तान की बैकग्राउन्ड से और संस्कृति से अलग है । अब मैं इस मौके पर इस बहस में नहीं जाता हालांकि यह बड़ी दिलचस्प बहस है कि ऐसी कौमों के लोगों से किस ढंग से बर्ताव होना चाहिए । अब बाज लोग तो उनको मौडर्नाइज किया चाहते हैं बड़ी तेजी से और बाज लोग उनको रखा चाहते हैं अजायबघर में । यह दो चीजें हैं । मेरी राय में यह दोनों चीजें गलत हैं । अजायबघर में रखना भी गलत है और मौडर्नाइज करना भी ठीक न होगा । अब मौडर्नाइज करने के मानी क्या होते हैं । उसके लिए पहले तो बनिये की दुकान वहां पर खोल और वह अपने कपड़े बेचें और उनका सारा आर्ट और कल्चर खत्म कर दिया जाय । उनको एक्स्प्लाएट किया जाय और वह एक ओपेन मार्केट हो जाय । फिर जैसे कि हमारे कुछ अफसरों की भी राय थी कि उनको ब्वाय स्काउट का काम सिखाया जाय । अब आप ही सोचिये कि ब्वाय स्काउट का काम उनको सिखलाना चाहते हैं जो कि जंगल के रहने वाले हैं और जो कि हजार गुना हम से वहां के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं और उनको सिखायेंगे ब्वाय स्काउट्स कि कसे जंगल में वे रहें तो यह तो एक निकम्मी बात और बेमानी बात होगी । इसी तरह यह जो हमारे लाक्स हैं, कम्युनिटी डवैलपमेंट ब्लाक्स हैं, अब उनकी बाबत वहां वे सरकुलर्स निकलते हैं और जो कि हिनयत मौजूं हो और जगहों के लिए लेकिन जब वही सरकुलर नागा हिल्स में पहुंचता है या नेफा में पहुंचता है तो वहां के लिए वह बिलकुल नामौजूं है । उस जगह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और पहले जो

वहां भेजा सो गलती हो गई लेकिन अब उसकी रोकथाम हो गई । तो यह दिक्कतें होती हैं ।

मेरा खयाल है कि वैरियर ब्लेबिन ने जो इस बारे में किताब लिखी है और उसमें जिक्र किया है और मैंने उसकी प्रस्तावना लिखी है अगर आपको दिलचस्पी हो जानने के लिए कि हमारी नीति हमारी फिलासफी क्या है उस ऐरिया में तो वह किताब यहां लाइब्रेरी में रखी हुई है उसको उठा कर पढ लें और मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर पढ़ें क्योंकि उस किताब में इन बातों पर काफी बहस हुई है । यह कोई आज की किताब नहीं है बल्कि वह चार, पांच वर्ष पहले की लिखी हुई है ।

जहां तक श्री जयपाल सिंह का ताल्लुक है मैं उनकी राय की बड़ी कद्र करता हूं और इस वक्त वह शिलांग में ट्राइबल एफेयर्स के हमारे औफिशिएल ऐडवाइजर हैं । मुझे खुशी है कि यह बहस हुई क्योंकि इससे कुछ ज्यादा रोशनी इस मसले पर पड़ी है । अब कांस्टीट्यूशन के एमेंड करने की बात सामने आई है ।

श्री राजपेयी : अध्यक्ष महोदय, म उन माननीय सदस्यों को और प्रधान मंत्री महोदय जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है, धन्यवाद देता हूं । यह सन्तोष की बात है कि उन्होंने इस गलत फेहमी को दूर किया है कि नागा लैंड का कोई अलग कांस्टीट्यूशन नहीं होगा । जो भी संविधान बनेगा इस संसद् में बनेगा । इस संसद् के बाहर नहीं बनेगा । मैं समझता हूं कि नागा नेताओं ने यहां से लौटने के बाद जो बातें कही हैं उनके कारण यह गलतफहमी पैदा हुई और अब उस का निराकरण हो जाना चाहिए । यह भी सन्तोष की बात है कि उन्होंने अनुभव किया कि हमारे राज्यों में जो किसी प्रकार की टीमटाम अधिक हो गई है उसको कम किया जाना चाहिए । वह टीमटाम केवल राज्यों में ही नहीं है बल्कि वह नई दिल्ली में भी है । इस टीमटाम में भी थोड़ी सी कमी करने की जरूरत है ।

माननीय सदस्यों ने जो भाषण किये उनसे कम से कम मेरी इस आशंका की पुष्टि हो गई कि भले ही नागा लैंड प्रधान मंत्री के कथनानुसार कोई एक नया राज्य न बनाया गया हो मगर उससे देश में छोटे छोटे राज्यों की मांग को बल मिलेगा और अगर आम आदमी यह समझे कि हमारा अलग राज्य बन जायगा तो उसकी गलती नहीं है क्योंकि इस विवाद में जिन सदस्यों ने भाषण दिये उनमें किसी ने ने तो पंजाबी सूबे की वकालत की है तो किसी ने झार खंड की वकालत की है और किसी ने हिल स्टेट की मांग की है । अब अगर संसद् सदस्य भी यह समझते हैं कि जो नागा लैंड बना है उसके आधार पर और भी राज्य बनने चाहिएं तो मैंने भी तो यही कहा था । इससे फिर आम आदमी को भड़काने में कितनी सहायता मिलेगी, इसका विचार करना चाहिए । मगर मुझे विश्वास है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसके आगे अब देश का और अधिक विघटन, पुनर्गठ न के नाम पर नहीं किया जायगा और हमें आशा करनी चाहिए कि नागा प्रदेश में शांति स्थापित होगी और वहां के लोग शेष भारतवासियों की तरह भारत के नागरिक की भाँति से और भारतमाता के पुत्र के नाते एक समान संस्कृति के उत्तराधिकारी के रूप में देश के विकास में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे ।

Mr. Speaker: The House will now stand adjourned till 11 A.M. tomorrow.

17.18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 19th August, 1960/Sravana 28, 1882 (Saka).